सोशल मीडिया से जुड़ें

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

आप में कितनी भी प्रतिभा क्यों न हो, प्रयास और अभ्यास के बिना सब व्यर्थ है !

वर्ष 01, अंक 256, नई दिल्ली

सोमवार, 27 नवम्बर 2023, मूल्य ₹ 5, पेज 8

कब चालू होगा द्वारका एक्सप्रेस-वे का गुरुग्राम का हिस्सा? सामने आई बड़ी जानकारी

संजय बाटला

गुरुग्राम भाग के भी दिसंबर तक चालू होने की उम्मीद नहीं। गुरुग्राम भाग में कई जगह निर्माण कार्य बाकी है ही गुरुग्राम सीमा से आगे यानी दिल्ली इलाके में निर्माण कार्य अधूरा होने से वाहन आगे जा नहीं सकते। प्रोजेक्ट के चालू होने से लगभग 10 लाख लोगों को सीधा लाभ होगा। इससे 40 प्रतिशत तक ट्रैफिक का दबाव कम होने की उम्मीद है।

गुरुग्राम। केंद्रीय भूतल सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस साल के भीतर द्वारका एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूरा कराने का दावा किया था, लेन जमीनी हकीकत यह है कि गुरुग्राम भाग के भी दिसंबर तक चालू होने की उम्मीद नहीं। गुरुग्राम भाग में कई जगह निर्माण कार्य बाकी है ही, गुरुग्राम सीमा से आगे यानी दिल्ली इलाके में निर्माण कार्य अधूरा होने से वाहन आगे जा नहीं सकते।

ऐसे में गुरुग्राम भाग को चालू करने का विशेष लाभ नहीं मिलेगा। जानकार बताते हैं कि यदि दिल्ली इलाके में फिलहाल द्वारका एक्सप्रेस-वे के गुरुग्राम भाग को नजफगढ़-बिजवासन रोड से जोड़ दिया जाए तो वाहन आगे निकल जाएंगे। दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे पर से ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए द्वारका एक्सप्रेस-वे का निर्माण खेड़कीदौला टोल प्लाजा से लेकर दिल्ली के महिपालपुर में शिवमूर्ति के सामने तक किया जा रहा है।

चार भागों में बांटा गया प्रोजेक्ट

प्रोजेक्ट को चार भागों में बांटा गया है। दो भाग गुरुग्राम इलाके में है, जबकि दो भाग दिल्ली इलाके में है। गुरुग्राम इलाके के दोनों भागों को मई में ही चालू करने का लक्ष्य रखा गया था। पूरा प्रोजेक्ट यानी गुरुग्राम से दिल्ली तक इस साल के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। इसकी घोषणा स्वयं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ महीने पहले एक्सप्रेस-वे के निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से बातचीत में की थी।

दिसंबर तक चालू होने की उम्मीद नहीं

पूरे प्रोजेक्ट की बात दूर गुरुग्राम भाग के भी दिसंबर तक चालू होने की उम्मीद नहीं। अभी धनवापुर के सामने अंडरपास का निर्माण पूरा होने में समय लगेगा। दौलताबाद के सामने निर्माण कार्य चल रहा है। सेक्टर-106 के सामने भी निर्माण कार्य अधूरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि गुरुग्राम भाग का निर्माण पूरा भी कर लिया जाए तो जब तक गुरुग्राम सीमा से आगे यानी दिल्ली इलाके में वाहनों के निकास की व्यवस्था नहीं होती तब तक कोई लाभ नहीं।

द्वारका एक्सप्रेस-वे वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष याशीश यादव कहते हैं कि एनएचएआई की कार्यशैली से लोगों को बहुत निराशा हाथ लगी है। एक बार नहीं कई बार लक्ष्य निर्धारित किया गया। एनएचएआई गुरुग्राम सीमा से आगे दिल्ली सीमा में द्वारका एक्सप्रेस-वे को फिलहाल नजफगढ़-बिजवासन रोड से जोड़कर गुरुग्राम भाग को चालू कर दे।

एक नजर में पूरा प्रोजेक्ट

द्वारका एक्सप्रेस-वे देश का सबसे छोटा एक्सप्रेस-वे है।

18.9 किलोमीटर हिस्सा गुरुग्राम में जबकि 10.1 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली में है।

23 किलोमीटर भाग एलिवेटेड और लगभग चार किलोमीटर भूमिगत (टनल) होगा।

काम तेजी से हो इसके लिए गुरुग्राम एवं दिल्ली के हिस्से को दो-दो भाग में बांटा गया है।

गुरुग्राम के दोनों भागों के निर्माण की जिम्मेदारी एलएंडटी नामक कंपनी के पास है।

दिल्ली के दोनों भागों के निर्माण की जिम्मेदारी जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के पास है।

दिल्ली में पहला भाग गुरुग्राम-दिल्ली सीमा से बिजवासन तक लगभग 4.20 किलोमीटर का है।

दिल्ली में दूसरा भाग बिजवासन से महिपालपुर में शिवमूर्ति तक 5.90 किलोमीटर का है।

गुरुग्राम इलाके में पहला भाग खेड़कीदौला टोल प्लाजा के नजदीक से बसई-धनकोट के नजदीक तक है।

गुरुग्राम में दूसरा भाग बसई-धनकोट के नजदीक से गुरुग्राम-दिल्ली सीमा तक 10.2 किलोमीटर का है।

दिल्ली एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए द्वारका इलाके में 3.6 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है।

द्वारका एक्सप्रेस-वे का एलिवेटेड हिस्सा सिंगल पिलर के ऊपर बनाया जा रहा है।

दो लाख एमटी स्टील का इस्तेमाल होगा, जो एफिल टावर के निर्माण की तुलना में 30 गुना अधिक।

20 लाख सीयूएम कंक्रीट का इस्तेमाल होने का अनुमान है जो बुर्ज खलीफा की तुलना में छह गुना अधिक।

10 लाख लोगों को सीधा फायदा

प्रोजेक्ट के चालू होने से लगभग 10 लाख लोगों को सीधा लाभ होगा। यही नहीं दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे से 40 प्रतिशत तक ट्रैफिक का दबाव कम होने की उम्मीद है। द्वारका एक्सप्रेस-वे को दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे एवं सदर्न पेरिफेरल रोड (एसपीआर) से जोड़ने के लिए खेड़कीदौला के नजदीक फुल क्लोवरलीफ फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। एसपीआर एक तरफ जहां गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड से जुड़ा है वहीं दूसरी तरफ दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे से जुड़ा है।

द्वारका एक्सप्रेस-वे का गुरुग्राम हिस्सा अगले साल जनवरी के दौरान हर हाल में चालू कराने का प्रयास है। वैसे जितनी जल्द चालू हो जाए वह अच्छा है। इसके चालू होने से लाखों लोगों को राहत मिलेगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं लगातार एनएचएआइ के वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हूं।

– निशांत कुमार यादव, उपायुक्त, गुरुग्राम

सड़क सुरक्षा: शराब पीकर गाड़ी चलाई तो यमराज आएंगे डिलिवरी लेने, परिवहन विभाग ने वीडियो जारी कर दिया संदेश

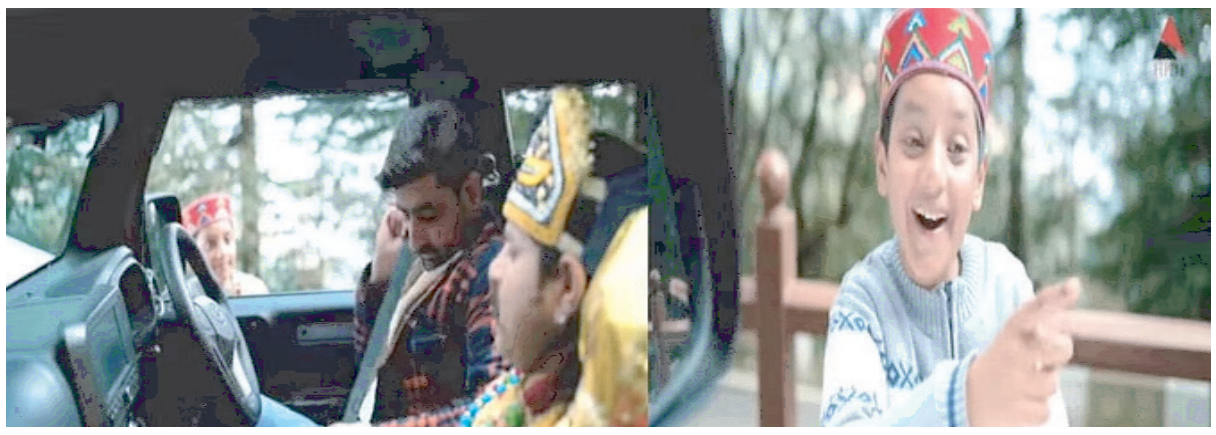

परिवहन विशेष न्यूज

परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर तैयार किए गए वीडियो में शराब पीकर गाड़ी न चलाने का संदेश दिया गया है।

नई दिल्ली। शराब पीकर गाड़ी चलाई तो डिलिवरी लेने खुद यमराज आएंगे। परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर तैयार किए गए वीडियो में शराब पीकर गाड़ी न चलाने का संदेश दिया गया है। वीडियो में कौन बनेगा करोड़पति फेम शिमला के अरुणोदय ने अभिनय किया है। शिमला में ही वीडियो शूट किया गया है। संदेश दिया गया है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से किसी और को न सही, लेकिन आपके परिवार जनों को जरूर फर्क पड़ेगा।

रिश्तेदार आपकी तेरहवीं में आएंगे और स्वादिष्ट खाना खाकर लौट जाएंगे। परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने बताया कि लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक करने के लिए वीडियो संदेश तैयार किया गया है। लोगों को आकर्षित करने के लिए अरुणोदय से अभिनय करवाया गया है। परिवहन विभाग के सोशल मीडिया पेज पर वीडियो जारी करने के महज 20 घंटों के भीतर ही यह हिमाचल के साथ देश-विदेश तक करीब 10 हजार लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। 250 से अधिक लोगों ने इसे शेयर किया है।

मंत्रालय ने दिसंबर 2015 में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के लिए कड़े उत्सर्जन मानक स्थापित किए, जिनका दो साल के भीतर अनुपालन करना आवश्यक था। बाद में इसने दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर सभी बिजली संयंत्रों को पांच साल का विस्तार दिया, जो क्षेत्र के उच्च प्रदूषण स्तर के कारण अनुपालन के लिए 2019 तक दिया गया था।

कोयला आधारित बिजली संयंत्र दिल्ली-एनसीआर में बढ़ा रहे प्रदूषण, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

दिल्ली-एनसीआर में ताप ऊर्जा संयंत्रों द्वारा उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं किए जाने से क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। एक नए विश्लेषण में यह जानकारी सामने आई है।

एक नए विश्लेषण के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में थर्मल पावर प्लांटों द्वारा उत्सर्जन मानकों का अनुपालन न करने से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। पर्यावरण से जुड़े थिंक टैंक. सेंटर फॉर साइंस एंड इंवायरमेंट (सीएसई) ने दिल्ली-एनसीआर में 11 ताप ऊर्जा संयंत्रों (टीपीपी) से उत्सर्जित प्रदूषक तत्वों, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक अध्ययन किया है। यह अध्ययन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की वेबसाइट पर मौजूद अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक की उनकी पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट पर आधारित है। सीएसई में रिसर्च एंड एडवोकेसी की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉय चौधरी ने बताया कि 'दिल्ली-एनसीआर में पीएम 2.5 प्रदूषण में टीपीपी का योगदान लगभग आठ प्रतिशत है। यदि प्रदूषण के निरंतर स्रोत, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट, उच्च स्तर पर प्रदूषकों का उत्सर्जन जारी रखते हैं तो दिल्ली-एनसीआर स्वच्छ वायु बेंचमार्क हासिल नहीं कर सकता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर सकता है। सीएसई की रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कई समय सीमा विस्तार और संशोधित वर्गीकरण के बावजूद, क्षेत्र के कई संयंत्र नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

यूपी: डीएल की तरह अब गाड़ी की आरसी भी होगी स्मार्ट, कार्ड सुरक्षा की दृष्टि से होगा अभेद्य

परिवहन विशेष न्यूज

वर्तमान में जो आरसी है उसे कॉपी किया जा सकता है, लेकिन स्मार्ट आरसी कार्ड सुरक्षा की दृष्टि से अभेद्य होगी। स्मार्ट डीएल की तरह ही स्मार्ट आरसी में भी माइक्रोप्रोसेसर लगेगा।

लखनऊ। परिवहन विभाग अब स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) की तरह ही स्मार्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) जारी करेगा। यह स्मार्ट डीएल के आकार और सुरक्षा उपायों से परिपूर्ण होगी। केंद्र सरकार से पहले ही स्मार्ट आरसी कार्ड जारी करने की अनुमति मिल गई है। अब राज्य सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में प्रतिमाह औसतन चार लाख आरसी जारी की जाती हैं। दूसरे राज्यों में स्मार्ट आरसी कार्ड की सुविधा मिल रही है। यूपी में यह व्यवस्था काफी देर से शुरू करने के प्रयास हो रहे हैं। प्रमुख सचिव परिवहन ने इस संबंध में सभी संभागीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश भेजे हैं। उम्मीद है कि नए साल से यह सुविधा शुरू हो जाए। परिवहन विभाग के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (आईटी) सगीर अहमद अंसारी ने बताया कि स्मार्ट आरसी जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में वाहन स्वामियों को स्मार्ट आरसी कार्ड दिया जाएगा।

ये होगी खासियत

सूत्र बताते हैं कि वर्तमान में जो आरसी है उसे कॉपी किया जा सकता है, लेकिन स्मार्ट आरसी कार्ड सुरक्षा की दृष्टि से अभेद्य होगी।

स्मार्ट डीएल की तरह ही स्मार्ट आरसी में भी माइक्रोप्रोसेसर लगेगा। इसमें वाहन स्वामी की सभी जानकारियां होंगी। वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर से लेकर वाहन की फिटनेस, पॉल्यूशन, कलर, वाहन का प्रकार, चेसिस नंबर जैसे सभी जरूरी जानकारियां दर्ज होंगी।

डीलर देंगे आरसी नंबर, घर पहुंचेगा कार्ड

डीलर रजिस्ट्रेशन अभी शोरूम पर होते रहे हैं, प्रमाणपत्र वहीं से जारी होते रहे हैं। लेकिन अब वे पंजीयन पत्रावलियां अपने पास नहीं रखेंगे। नई व्यवस्था के तहत वाहनों के डीलर आरसी जारी नहीं करेंगे, बल्कि वाहन स्वामी को आरसी का नंबर देंगे। एआरटीओ कार्यालय की तरफ से वाहन स्वामी के पते पर पोस्ट ऑफिस के जरिये स्मार्ट कार्ड आरसी उनके घर पहुंचेगा।

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

तेज रफ्तार बाइक नहर के पुल पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, दो की मौत

परिवहन विशेष न्यूज

हादसे में रात को घूमने निकले बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस दोनों को अस्पताल ले गई। जहां डॉक्टर ने अर्नब सरकार (20) को मृत घोषित कर दिया। वहीं इलाज के दौरान कुछ देर बाद दूसरे युवक आयुष मंडावत (20) ने भी दम तोड़ दिया।

नई दिल्ली। समयपुर बादली इलाके में तेज रफ्तार बाइक नहर के पुल पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में रात को घूमने निकले बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस दोनों को अस्पताल ले गई। जहां डॉक्टर ने अर्नब सरकार (20) को मृत घोषित कर दिया। वहीं इलाज के दौरान कुछ देर बाद दूसरे युवक आयुष मंडावत (20) ने भी दम तोड़ दिया।

हादसे के वक्त दोनों ने हेलमेट पहन रखे थे। पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने से हुई मौत का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अर्नब पिता मृत्युंजय सरकार समेत परिजनों के साथ द्वारका इलाके के जैन रोड में रहता था। जबकि आयुष दौसा राजस्थान निवासी था।

बृहस्पतिवार रात करीब दोनों सुजुकी जिक्सर बाइक से घूमने निकले थे। समयपुर बादली के नहर वाले पुल पर रात करीब एक बजे तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने अर्नब को मृत घोषित कर दिया। जबकि इलाज के दौरान आयुष ने दम तोड़ दिया।

बाइक के नंबर के जरिये पुलिस को पता चला कि बाइक मृत्युंजय के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस के संपर्क करने पर मृत्युंजय कहा कि बेटे अर्नब के बाइक चलाने की बात कही। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आयुष के आने के बाद अर्नब खाना खाने के बाद उसे बाइक से लेकर घूमने के लिए निकला था। इसी दौरान उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद अर्नब

तेज रफ्तार कार सवार ने छह लोगों को मारी टक्कर, इलाज के दौरान एक की हुई मौत

नोएडा के सेक्टर 83 में शनिवार आधी रात को एक तेज रफ्तार कार सवार ने पैदल जा रहे छह लोगों को टक्कर मार दी। इसमें एक युवक की मौत हो गई और अन्य पांच घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है।

नोएडा के सेक्टर 83 में शनिवार आधी रात को एक तेज रफ्तार कार सवार ने पैदल जा रहे छह लोगों को टक्कर मार दी। इसमें एक युवक की मौत हो गई और अन्य पांच घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में कोतवाली फेस टू पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और अज्ञात कार की पहचान कर रही है। कोतवाली फेस 2 स्थित एक कंपनी में काम करने वाले छह लोग शनिवार देर रात करीब 1:15 बजे एप्पल कंपनी के सामने सेक्टर 83 में जा रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात कार चालक ने छह लोगों को टक्कर मार दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इनमें एक युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान मूल रूप से सीतापुर जनपद के लहरपुर गांव निवासी 22 वर्षीय इस्लाम के रूप में हुई है। नोएडा सेंट्रल जोन के एडीसीपी हृदयेश कठेरिया ने बताया की पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात कार व उसके चालक की पहचान की जा रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सही सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक किया जा रहा है।

योगी राज में नारियों के सशक्त होने से समृद्ध हो रहा है उत्तर प्रदेश

आज नया उत्तर प्रदेश सफलता की नई कहानी कह रहा है। सरकार ने समर्थ उत्तर प्रदेश के महिला श्रम शक्ति को सशक्त बना दिया है। इनकी समृद्धि के लिए सरकार संकल्पित है। महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार ने नवरात्रि के पावन अवसर पर मिशन शक्ति की चतुर्थ चरण का प्रारंभ किया है।

ऋचा सिंह

वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार मिशन शक्ति फेज 4 का प्रारंभ शक्ति वंदन कार्यक्रम के साथ कर रही है। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त बनाने एवं जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित कर महिलाओं, बालिकाओं से वार्ता कर उनके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। बालिकाओं, छात्राओं, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के साथ उन्हें सजग, सतर्क एवं निर्भीकता के साथ आत्मनिर्भर बनने एवं सम्मान के साथ अपने क्षेत्र में कार्य करने हेतु प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार का मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला स्वावलंबन के लिए उठाया गया कदम महिलाओं में ऊर्जा और उत्साह का संचार कर रहा है। पिछले 6 वर्षों में प्रदेश की महिलाओं की आत्मनिर्भरता एवं श्रम शक्ति में दोगुने से भी अधिक की वृद्धि हुई है। शहरी महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ-साथ ग्रामीण अंचल की महिलाओं में भी उत्साह बढ़ रहा है। ग्रामीण महिलाओ में समूह के द्वारा कार्य करने की भावना पहले की अपेक्षा बढ़ी है।

लगभग 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाकर उससे एक करोड़ महिलाओं का जुड़ना एक बड़ी उपलब्धि की ओर इशारा करती है जो महिलाओं के सम्मान पूर्वक जीने एवं उनके स्वावलंबी बनने का उदाहरण है। यह इस बात को भी दर्शाता है कि आगे चलकर प्रदेश की आर्थिक समृद्धि में महिलाओं की सशक्त भागीदारी होगी। महिलाएं अपने घर एवं परिवार के सभी सदस्यों के पोषण की स्वीकृति के भाव के साथ होती हैं, ऐसी भूमिका में उन्हें परिवार एवं समाज की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। यदि समाज व परिवार का यह हिस्सा सम्मान के साथ आत्मनिर्भर हो तो निश्चित रूप से समाज ही समृद्धि की ओर कदम बढ़ाकर स्वावलंबन की ओर बढ़ता है। राज्य सरकार के दिशा निर्देश में मिशन शक्ति फेज 1 के प्रारंभ के साथ ही महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता हेतु कई कदम उठाए गए थे जिसका यह स्वर्णिम प्रतिफल है कि महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं एवं बालिकाएं शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं। राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार 2017-18 में श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी 14.9% थी जो अब 36.5 प्रतिशत हो गई है।

राज्य सरकार की योजना का ही परिणाम है कि महिलाएं आज प्रदेश में नए कीर्तिमान गढ़ रही हैं। ऐसा दिखाया गया है कि बहुत सारी योजनाएं लागू की जाती हैं लेकिन वह जिनके लिए उपयोगी हैं उस स्तर तक उस व्यक्ति तक वह योजनाएं पहुंच ही नहीं पाती थीं जिनसे उन योजनाओं का लाभ से लाभार्थी व्यक्ति वंचित रह जाता था। मिशन शक्ति के अंतर्गत इन योजनाओं को ग्रामीण अंचल से लेकर के शहरी क्षेत्र में एक समान रूप से लोगों तक जन-जन तक पहुंचाया गया है। वर्तमान में मिशन शक्ति फेस 4 जो नवरात्र के प्रथम दिवस पर प्रारंभ किया गया है इसमें विद्यालय से भी रैली निकाली गई, हर संस्थाओं और विभाग से इसे जोड़ा गया। सुरक्षा, स्वावलंबन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली महिलाओं को पुरस्कृत किया गया है और यह एक अभियान बनाकर विद्यालय से लेकर के जिला स्तर तक के बड़े कार्यालय से जोड़ा गया है जिससे मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं को सशक्त करने हेतु किए गए प्रयास हर महिला तक, हर बालिका तक पहुंच सकें और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इससे लाभान्वित हो सकें।

मिशन शक्ति अभियान कार्यक्रम से महिलाओं और बेटियों को स्वयं के अधिकारों को जानने के साथ उनमें एक चेतना जागृत हुई है। कन्या सुमंगला प्रोग्राम, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रोग्राम, मिशन शक्ति प्रोग्राम के अंतर्गत बालिकाओं और महिलाओं को एक अवसर प्रदान किया गया जिससे वह सम्मानित और सशक्त महसूस कर सकें। ग्राम पंचायत में बीसी सखी और पीएम सम्मान निधि योजना के तहत 2 लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया जाना ऐसे ही अवसर थे जो महिलाओं को प्रदान किए गए। वर्तमान समय में प्रदेश की महिलाओं ने श्रम शक्ति में मिले अवसरों का उपयोग कर अपने लिए स्वर्णिम भविष्य गढ़ दिया है।

आज कला, विज्ञान, अंतरिक्ष, व्यापार, शिक्षा हर क्षेत्र में बालिकाएं आगे निकल रही हैं ऐसे में

किसी अवांछनीय तत्व से बिना डरे मिशन शक्ति अभियान के द्वारा बच्चियां, महिलाएं निडर होकर घर से बाहर निकल रही हैं। मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रदेश भर में चल रही महिला संबंधी योजनाएं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, बीसी सखी, प्रधानमंत्री वंदन योजना आदि का व्यापक प्रचार प्रचार भी किया जा रहा है। जिससे महिलाएं इन योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ उठा सकें। इन योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु कैंप लगाकर भी अभियान चलाए जा रहे हैं। महिलाओं और बालिकाओं को शासन सुरक्षा संबंधी सेवाएं जैसे विभिन्न पावर लाइन, महिला हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, पुलिस आपातकालीन सेवा, चाइल्ड हेल्पलाइन, चिकित्सा संबंधी स्वास्थ्य सेवा, एंबुलेंस सेवा संबंधी जानकारी को जगह जगह पेंट करा कर लिखवाया जा रहा है जिससे जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा गठित महिला सुरक्षा बल गांव में जन चौपाल लगाकर, बस स्टैंड, बाजार, गांव, कस्बा, स्कूल कॉलेज, सार्वजनिक एवं भीड़भाड़ वाले स्थान पर बालिकाओं महिलाओं से वार्ता कर महिला सुरक्षा संबंधी उपायों के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। शक्ति दीदी के रूप में महिलाओं से जुड़कर उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मिशन शक्ति का उद्देश्य प्रत्येक नारी और बच्चियों को सुरक्षा तथा सम्मान का अधिकार दिलाना है, उन्हें सरकार की योजनाओं से अवगत कराते हुए जागरूक करना, मानसिक रूप से सबल व सामान बनाते हुए प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें अवसर प्रदान करना है। मिशन शक्ति ने पूर्व में तीन चरणों में अपार सफलता हासिल की तथा इसका सफल क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में किया गया है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नारी वंदन अधिनियम के तहत नारियों को सम्मान व सुरक्षा प्रदान किया गया है। आज महिलाएं सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित नहीं हैं, आज ऐसा नहीं है कि वह ग्रामीण अंचल से हैं तो उनको अवर नहीं उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनकर समाज के पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर आत्मनिर्भर बनते हुए अपने परिवार को आर्थिक एवं सामाजिक सहायता प्रदान कर रही हैं।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत फेज 4 में ऐसी छात्राएं जो विद्यालय से दूर हो रही हैं उन्हें चिन्हित करके उनके अभिभावकों से संपर्क कर उन्हें पावर एंजेल के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है और सघन अभियान चलाकर छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। बाल अधिकारों के साथ-साथ उन्हें जरूरी कानून के बारे में जानकारी दी जारही एवं सजग एवं सतर्क बनने के लिए दृष्टि प्रदान की जा रही है।

आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश सफलता की नई कहानी कह रहा है। सरकार ने समर्थ उत्तर प्रदेश के महिला श्रम शक्ति को सशक्त बना दिया है। इनकी समृद्धि के लिए सरकार संकल्पित है। महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार ने नवरात्रि के पावन अवसर पर मिशन शक्ति की चतुर्थ चरण का प्रारंभ किया है। नारी सुरक्षा नारी सम्मान के साथ स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रही है। शारदीय नवरात्रि से निरंतर अनेक कार्यक्रम अयोजित हो रहे हैं। केंद्र सरकार की महिला संबंधित योजनाओं का प्रदेश सरकार पारदर्शी ढंग से शत प्रतिशत लाभ महिलाओं को मिल रहा है। सरकार के कुशल नेतृत्व एवं मॉनिटरिंग का ही परिणाम है कि महिलाओं के श्रम बल की भागीदारी में वृद्धि हुई है। सरकार के मार्गदर्शन में महिलाओं के उत्थान पर विशेष रूप से कार्य किया गया है जिसकी सीएम ने स्वयं मॉनिटरिंग भी की है। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 1.90 करोड़ बेटियों को जागरूक किया गया है। मिशन शक्ति अभियान के तहत 8.99 करोड़ महिलाओं को जागरूक किया गया है। 189789 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए इनमें से 189014 केंद्र संचालित भी हैं। 10 लाख सेल्फ ग्रुप बनाकर एक करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया 2 लाख से अधिक महिलाओं को पीएम सम्मांन निधि योजना से लाभान्वित किया गया। सभी 57000 से अधिक ग्राम पंचायत में बीसी सखी की नियुक्ति की गई। सरकारी नौकरियों में भी डेढ़ लाख से अधिक महिलाओं को यूपी में नौकरी से जोड़ा गया, साथ ही अन्य सभी योजनाओं से महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

मिशन शक्ति अभियान के तहत गांव में चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। चौपाल में महिलाओं, बालिकाओं को उनके अधिकार बताए जा रहे हैं साथ ही विभिन्न कानून के साथ ही सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। मिशन शक्ति फेज 4 में शक्ति दीदी अभियान के तहत चौपाल का आयोजन करके महिलाओं को सम्मानित प्रोत्साहित व सुरक्षित किया जा रहा है। सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री निराश्रित महिला पेंशन योजना की जानकारी चौपाल के माध्यम से दी जा रही है इसके साथ ही महिला संबंधी अपराधों के रोकथाम व त्वरित सहायता के लिए विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों को डायल करने के लिए उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और जगह जगह पर इसे लिखवाया जा रहा है। बालिकाएं शिक्षा से वंचित न हो इसके लिए बाल श्रम, बाल विवाह आदि के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है।

लेखिका– बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में शिक्षिका हैं।

पुस्तक समीक्षा : बाल अधिकार जगाती 'पोशम्पा'

एक दौर था, जब गली-मुहल्ला ही नहीं, घर-आँगन भी बच्चों के खेलों और उनकी चिल्ल-पों से भरा रहता था। कहीं लट्टू, कंचे, तो कहीं चष्टांग-अष्टांग, गिल्ली-डंडा, स्टापू, रस्सी, चोर-पुलिस, मंत्री सिपाही और शतरंज आदि शारीरिक एवं मानसिक खेलों का जमावड़ा लगा रहता था। तब बाल जीवन में बोरियत शब्द का कोई स्थान नहीं था। बच्चे सीमित सुविधाओं में भी खुलकर जीना जानते थे, पर आज जीवन में अनेक सुविधाओं के होते हुए भी बालमन उबाऊ और नीरसता का अनुभव कर रहे हैं। इसी उबाऊ और नीरसता को दूर करने एवं बाल अधिकारों के प्रति सबको जागरूक करने का एक बेहतरीन प्रयास 'पोशम्पा' पुस्तक है। इसके जरिए जनमानस और सरकार को बताया गया है कि, बाल अधिकारों का सरंक्षण अवश्य किया जाए।

साहित्य अकादमी म.प्र. से अभा स्तर पर पुरस्कृत और साहित्य संग सामाजिक कार्यों में योगदान देने वाले इंदौर के लेखक अजय जैन 'विकल्प' के सम्पादन में 'पोशम्पा' पुस्तक का आकार प्राप्त कर पाई है। यह काव्य संग्रह पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला (देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर) तथा 'यूनिसेफ' के सहयोग से सबको सचेत करने की दिशा में अभियान के रूप में हिन्दीभाषा.कॉम द्वारा प्रकाशित की गई है।

'पोशम्पा' की यात्रा सम्पादक की वाणी से आरंभ होती है। 'पोशम्पा' साहित्य अकादमी म.प्र. के निदेशक डॉ. विकास दवे, महाराष्ट्र साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शीतला प्रसाद दुबे, 'वसुधा' पत्रिका (कनाडा) की सम्पादक डॉ. स्नेहा ठाकुर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. रेनू जैन, राष्ट्रीय बाल साहित्यकार डॉ. दिविक रमेश (नोएडा) सहित अनेक वरिष्ठ साहित्यकारों की शुभकामनाओं एवं अभिनंदन से फलीभूत है।

इस संकलन (मूल्य-१५० ₹, पृष्ठ संख्या-१०४ (पेपर बैक), प्रकाशक-लक्ष्मी प्रकाशन, दिल्ली-बनारस) को कुल ४ कवियों की एकल कविताओं से रचाने का प्रयास किया गया है। बच्चों को प्रोत्साहित एवं मार्गदर्शित करने वाले सरल शीर्षक जैसे 'करो मनन', 'क्या ये उनका अधिकार नहीं', 'सर्वप्रथम अधिकार इन्हीं का', 'नई कहानी', 'कैसे देश बढ़ेगा आगे', 'छोटे बच्चे और समाज के दायित्व', 'शोषण से है बचाना', 'अब तो मुनिया खूब पढ़ेगी', 'चाहिए अधिकार' आदि संकलित किए गए हैं, किन्तु बालमन और उसके अधिकार की पूर्ण गम्भीरता को दिखाया गया है।

बात करें रचनाओं की, तो मुम्बई की बाल कवयित्री शर्विल सावंत की रचना में प्रतीकात्मकता द्रष्टव्य होती है-"खिलौनों से खेलने की उमर,
पर बांधी इन्होंने ईंटों से कमर
राहत माँगे कर इनके,
तो क्या ये उनका अधिकार नहीं ?"

इसमें बालमन के अधिकारों की बात कितनी सहजता से व्यक्त की गई है, समझा जा सकता है। कवयित्री वर्तमान स्थिति को व्यक्त कर संपूर्ण समाज को सोचने पर विवश करती है।

माँ की लोरी हो या कहानी, सदा अपनत्व देती है और माँ से जुड़े रहने का एहसास कराती है। यही बात सुरेन्द्र सिंह राजपूत 'हमसफर' लिखते हैं-
"गीत एक मीठा सा गाकर,
परी लोक ले जाओ न।
अम्मा एक नई कहानी,
मुझको आज सुनाओ न..॥"

बच्चों को सदा से राजा-रानी, परियों आदि की

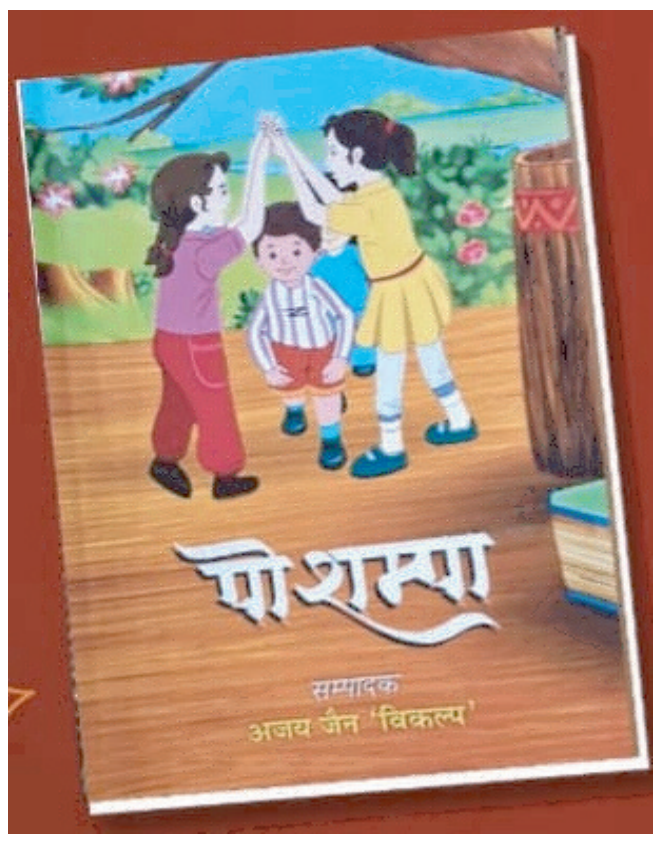

कहानियाँ प्रिय होने के साथ सुनना भी रोचक लगता है। सुरेन्द्र सिंह की पंक्तियों से यही भाव स्पष्ट होते हैं।

तारा चंद वर्मा 'डाबला' बच्चों को 'ईश्वर का उपहार' काव्य में उनके अधिकार की बात करते हुए लिखते हैं-
'बालक है जग का आधार,
लौटा दो उनका अधिकार
क्यों छीन ली उनकी हँसी,
क्यों मतलबी हुआ संसार ?'

उक्त कविता का शब्द-शब्द बच्चों के अधिकार की बात व्यक्त करता है। वास्तव में आज बच्चे मुस्कुराना भूलते जा रहे हैं। न जाने किस दुनिया में पलायन कर रहे हैं हमारे नन्हें बाल।

बेटियों की शिक्षा के अधिकार की बात करते हुए कवियित्री डॉ. वर्षा महेश 'गरिमा' (मुम्बई) 'अब तो मुनिया खूब पढ़ेगी' में लिखती हैं-
'चूल्हे-चक्की की खटपट से,
चकला-बेलन की लटपट से
चौके में पड़ी जली कढ़ाईयाँ नहीं घिसेगी,
अब तो मुनिया खूब पढ़ेगी।'

इस संग्रह की भाषा बड़ी सहज, सरल एवं प्रभावी है। पुस्तक का मुख्य एवं मलय पृष्ठ रंगीन, आकर्षक और बाल मन को प्रिय लगने वाला है। निश्चित ही यह काव्य कृतियाँ पाठकों को रिझाने वाली है। सभी कविताएँ रोचकता से परिपूर्ण हैं। कहीं-कहीं भाषागत मानक त्रुटियाँ देखने को मिली हैं, हो सकता है कि, प्रकाशक इस तथ्य से अनभिज्ञ हो। बाल प्रधान काव्य संग्रह ने मुझे प्रभावित किया है। सम्पादक तथा सभी रचनाकारों को ढेरों शुभकामनाएँ एवं बधाई। आपकी कलम सदा समाज हित में ऐसा ही सार्थक सृजन करती रहे, यही शुभेच्छाएँ।

समीक्षक -डॉ. पूजा अलापुरिया 'हेमाक्ष', मुंबई (महाराष्ट्र)

बेसन, सूजी लंबे समय तक रहेंगे फ्रेश, बस ट्राई करे लें ये किचन हैक्स

अक्सर लोग घर में बेसन, सूजी और मैदा को स्टोर करते हैं ताकि मूड होने पर गर्मागर्मा हलवा और पकौड़े का मजा ले सकें। लेकिन इसका मजा लेने के लिए जरूरी है कि आप सूजी, मैदा और बेसन जैसी चीजों को ठीक तरीके से स्टोर करें ताकि उसमें कीड़े ना पड़े और आपको उसको मजबूरी में फेंकना ना पड़े। जब मौसम बदल रहा होता है तब भी चीजों में कड़ी पड़ने का डर होता है। ऐसे में आप इन्हें सावधानी के साथ स्टोर करें, जिससे ये लंबे समय तक फ्रेश रह पाएगा....

बेसन, सूजी या मैदे को खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज में रखें। किसी एयर टाइट कंटेनर में इन चीजों को भरकर रख दें। इससे कभी कीड़े नहीं लगेंगे। फ्रिज में लंबे समय तक इन्हें स्टोर किया जा सकता है।

नीम की पत्ते रखें

सूजी, बेसन और मैदा को कीड़े से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां डाल कर रखें। नीम की पत्तियों को डालने से पहले उन्हें सुखा लें, उसके बाद ही किसी एयर टाइट कंटेनर में इसे डालकर रखें।

हल्का सा भून लें

बेसन और सूजी को कीड़े लगने से बचाने के लिए स्टोर करने से पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लें। लेकिन ध्यान रहे मैदे को भूनना नहीं है। इस तरह से बेसन और सूजी लंबे समय तक चलेगी।

'फंगल संक्रमण' के कारण क्या हैं?

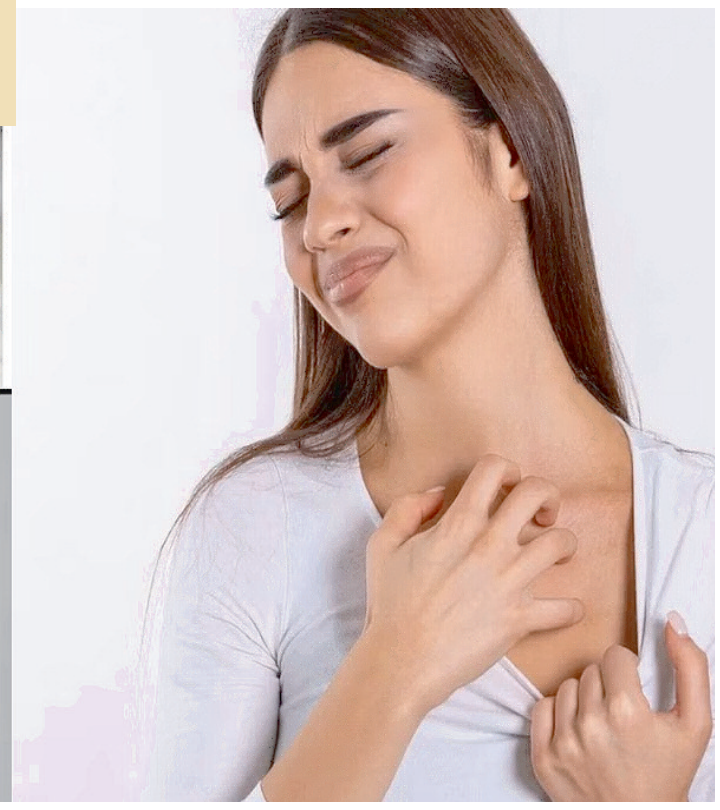

फंगल इंफेक्शन से पीड़ित लोगों की संख्या भी कम नहीं है। शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाला यह फंगल संक्रमण आपको एक समय के बाद पूरी तरह सदमे में डाल सकता है। लेकिन ऐसा क्यों है? किस बात का ध्यान रखा जा सकता है? आइए आज इसी के बारे में जानते हैं...

कारण क्या हैं?:

गर्म और आर्द्र वातावरण इस समस्या का कारण बनता है।

जिन लोगों को बहुत अधिक पसीना आता है उनमें फंगल संक्रमण होने का खतरा अधिक होता है।

गीले कपड़े पहनना।

तंग जूते या कपड़े पहनना।

लंबे समय तक मोज़े पहने रहना।

व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान न रखना।

एंटीबायोटिक दवाओं के दुष्प्रभाव

कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली

1. कैंडिडा अल्बिकन्स : यह एक फंगल संक्रमण है जो जननांगों के पास मुंह के पास की त्वचा, नम त्वचा पर होता है।

2. दाद : यह भी एक फंगल संक्रमण है। जो मुख्य रूप से त्वचा, खोपड़ी, पैरों, जांघों और जननांगों के पास होता है।

किस बात का ध्यान रखें?:

व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें।

बाथरूम या सार्वजनिक स्नान क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखें।

हर समय एक जैसे मोज़े न पहनें।

ज्यादा टाइट जूते न पहनें।

किसी का सामान प्रयोग न करें।

प्रभावित क्षेत्र पर दिन में 3-4 बार 2.5 PH के अम्लीय पानी का छिड़काव करना चाहिए।

आप स्थापना दिवस: मात्र 11 साल में राष्ट्रीय पार्टी तक का सफर, राजनीतिक करियर में देखे कई उतार-चढ़ाव

परिवहन विशेष। न्यूज

गठन के 11 साल में आम आदमी पार्टी ने कई बार उतार-चढ़ाव देखे हैं। आप ने 2014 का लोकसभा चुनाव देश की 400 सीटों पर लड़ा। केजरीवाल वाराणसी से नरेन्द्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े। इसके नतीजे अच्छे नहीं रहे। आप के हाथ कुछ नहीं लगा। दिल्ली में भी एक भी सीट नहीं मिली। आप सिर्फ पंजाब में चार सीटों पर जीत दर्ज कर सकी।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस आज है। आम आदमी पार्टी (आप) के गठन को भले ही अभी बहुत समय नहीं हुआ है, लेकिन गठन के 11 साल में ही आप ने अपने राजनीतिक करियर में कई बार उतार-चढ़ाव देखे हैं। कई प्रमुख नेताओं ने पार्टी छोड़ी या बाहर किए गए और कई राज्यों में दो-दो बार चुनाव लड़ने के बाद भी खाता नहीं खुल सका।

दो राज्यों में सरकार

दिल्ली में पहली बार सरकार बनाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को 49 दिन में इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन उसके बाद फिर से लगातार दो बार दिल्ली में बड़ी जीत के साथ सरकार बनाई।

दिल्ली में तीन बार सत्ता में आने के साथ ही आप (Aam Aadmi Party) पंजाब में भी सत्तासीन हुई और दिल्ली नगर निगम में भी कब्जा कर लिया है।

गिरफ्तारी को राजनीतिक षड्यंत्र बता रही AAP

आप अब राष्ट्रीय पार्टी भी बन गई है, मगर इस सब के साथ ही आप विवादों में भी रही है। पिछले कुछ सालों में यह विवाद और बढ़ गए हैं, आप नेताओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इस समय आप के तीन बड़े नेता जेल में हैं। हालांकि आप इस गिरफ्तारी को राजनीतिक षड्यंत्र बताती है।

आज के दिन हुई थी AAP की स्थापना, CM केजरीवाल बोले- हमारे जज्बे और जुनून में नहीं आई कोई कमी

CM केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को किया याद, बोले- पहली बार उनके बगैर मना रहा हूं AAP का स्थापना दिवस

आप की बात करें तो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए अन्ना आंदोलन से निकलकर आप का गठन 2012 में हुआ था आइआरएस अधिकारी रहे अरविंद केजरीवाल व उनके साथ के कुछ लोगों ने इसका गठन किया था। एक साल बाद ही 2013 में आम आदमी पार्टी ने पहला चुनाव लड़ा।

पहले चुनाव में मिलीं 28 सीटें

70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में आप दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसे 28 सीटें मिलीं। कांग्रेस ने उसे बाहर से समर्थन दिया और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बन गई, लेकिन यह सरकार अधिक दिनों तक नहीं चल सकी, 49 दिन बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया।

इसके बाद 2015 में हुए दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीतीं। फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में भी 70 में 62 सीटों पर जीत दर्ज की।

कई चुनाव बुरी तरह हारी

पंजाब की बात करें तो पंजाब में 2022 में 117 में से 20 सीटें हासिल कीं। आप के पास

गोवा में दो और गुजरात में पांच सीटें हैं।

वर्तमान में पार्टी के पास पूरे देश में 161 विधायक, एक सांसद और 10 राज्यसभा सदस्य हैं। दिल्ली नगर निगम में भी आप की सरकार है। हालांकि इन 10 साल में आप कई चुनाव बुरी तरह हारी भी है।

400 सीटों पर लड़ा 2014 का लोकसभा चुनाव

आप ने 2014 का लोकसभा चुनाव देश की 400 सीटों पर लड़ा। केजरीवाल वाराणसी से नरेन्द्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े। इसके नतीजे अच्छे नहीं रहे। आप के हाथ कुछ नहीं लगा।

दिल्ली में भी एक भी सीट नहीं मिली। आप सिर्फ पंजाब में चार सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से आप को झटका लगा, जब भाजपा ने फिर से दिल्ली की सातों लोकसभा सीटें जीत लीं।

यात्रा के दौरान पार्टी में अंतर्कलह आई सामने

पूरे देश में आप के पास पंजाब की केवल एक सीट बची। इस यात्रा के दौरान पार्टी में अंतर्कलह सामने आई। अप्रैल 2015 में पार्टी के संस्थापक सदस्यों योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और प्रो. आनंद कुमार को आप से निष्कासित कर दिया गया।

इसके बाद कुमार विश्वास, आशुतोष और आशीष खेतान भी पार्टी से अलग हुए। कपिल मिश्रा को मंत्री पद से हटाया गया तो मिश्रा ने शीर्ष नेतृत्व पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी।

AAP के तीन नेता जेल में

आबकारी नीति घोटाले मामले में आप के नेता व दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गत 26 फरवरी को गिरफ्तारी हुई थी, वह अभी तक जेल में हैं। इसके बाद इस नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गत चार अक्टूबर से आप से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह जेल में हैं।

इससे पहली फर्जी कंपनियों को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं। वैसे वे इस समस मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर हैं। मगर इसे जेल के खाते में ही गिना जा रहा है। इससे पहले फर्जी डिग्री मामले में आप सरकार में मंत्री रहे जितेंद्र सिंह तोमर और सीडी कांड मामले में मंत्री संदीप कुमार की भी गिरफ्तारी हुई थी।

11 साल में 'AAP' पर 250 से ज्यादा फर्जी केस, केजरीवाल बोले- किसी राजनीतिक पार्टी पर नहीं हुए इतने हमले

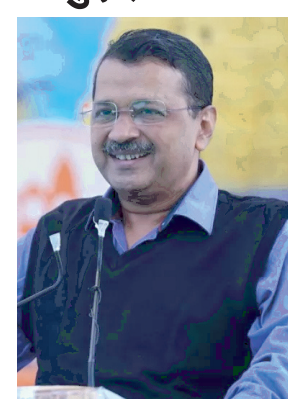

दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पार्टी के 11वें स्थापना दिवस पर कहा कि भारत के इतिहास में किसी भी पार्टी पर उतने हमले नहीं हुए जितने बीते 11 साल में आप को निशाना बनाया गया। इन 11 साल में 250 से अधिक फर्जी केस दर्ज किए गए। देश की सभी एजेंसियां आप के पीछे लगा रखी है। लेकिन अभी तक उन्हें एक भी हमारे खिलाफ सबूत नहीं मिला।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की स्थापना के 11 साल पूरे हो गए। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आप नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का भी जिक्र किया।

सीएम केजरीवाल ने कहा, 'भारत के इतिहास में किसी भी पार्टी पर उतने हमले नहीं हुए, जितने बीते 11 साल में 'आप' को निशाना बनाया गया। इन 11 साल में 250 से अधिक फर्जी केस दर्ज किए गए। देश की सभी एजेंसियां 'आप' के पीछे लगा रखी है। लेकिन अभी तक उन्हें एक भी हमारे खिलाफ सबूत नहीं मिला। यह हमारी ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रमाण है।'

11 साल में जुनून में नहीं आई कमी

केजरीवाल ने 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन शुरू की। इस दौरान समाजसेवी अन्ना हजारे के साथ कांग्रेस सरकार की भ्रष्टाचार को उजागर किया। इसके बाद से वह राष्ट्रीय चेहरा बन गए। केजरीवाल ने कहा कि आज ही के दिन साल 2012 में आम आदमी उठा और 'आम आदमी पार्टी' की स्थापना की। तब से लेकर आज तक कई उतार-चढ़ाव आए हैं। इन 11 सालों में कई मुश्किलें भी आई हैं, लेकिन हम सभी के जज्बे और जुनून में कोई कमी नहीं आई है।

लोगों के प्यार से AAP बनी राष्ट्रीय पार्टी

उन्होंने कहा कि आज लोगों के प्यार और आशीर्वाद से एक छोटी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी में बदल गई। लोगों का स्नेह हमारे साथ है और यही हमें लोगों की भलाई की दिशा में काम करने की ताकत देता है। AAP ने पार्टी की स्थापना के लिए 26 नवंबर की तारीख इसलिए चुना क्योंकि इसी दिन 1949 में संविधान अपनाया गया था। पार्टी की स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई।

सीएम केजरीवाल ने जेल में बंद मनीष सिसोदिया को किया याद, बोले- पहली बार उनके बगैर मना रहा हूं पार्टी का स्थापना दिवस

आज आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस है। इस खास मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने करीबी और दिल्ली पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को याद किया है। उन्होंने कहा कि झूठे मामलों में जेल में बंद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बिना पहला स्थापना दिवस मना रहा हूं।

नई दिल्ली। अन्ना आंदोलन के बाद साल 2012 में बनी आम आदमी पार्टी (आप) की स्थापना को 11 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अपने करीबी और दिल्ली पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को याद किया है।

अपनी पार्टी के स्थापना और संविधान दिवस पर उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में आज भारत का संविधान दिवस है। इसी दिन डॉ. बीआर अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए भारत के संविधान को अपनाया गया था। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारी पार्टी (आप) का गठन इसी दिन हुआ था।

आप के राष्ट्रीय संयोजक ने आगे कहा कि झूठे मामलों में जेल में बंद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बिना पहला AAP स्थापना दिवस मना रहा हूं। मुझे इस मौके पर उनकी याद आ रही है।

इससे पहले सीएम केजरीवाल ने अपने अधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आज ही के दिन साल 2012 में देश के आम आदमी ने उठकर अपनी खुद की पार्टी 'आम आदमी पार्टी' की स्थापना की थी। तब से लेकर आज तक इन 11 साल में बहुत उतार-चढ़ाव आए बहुत मुश्किलें भी आई, लेकिन हम सबके जज्बे और जुनून में कोई कमी नहीं आई है।

एक छोटी सी पार्टी को आज जनता ने अपने प्यार और आशीर्वाद से एक राष्ट्रीय पार्टी में बदल दिया है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम सब अपने मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और जनता के लिए काम करते रहेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

केजरीवाल बोले- हमारे जज्बे और जुनून में नहीं आई कोई कमी

आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस आज है। आज ही के दिन साल 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और Aam Aadmi Party के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर जज्बे और जुनून के साथ काम करते रहने की बात कही है।

नई दिल्ली। दिल्ली और पंजाब में सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी (आप) की स्थापना के आज 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर जज्बे और जुनून के साथ काम करते रहने की बात कही है।

आज ही के दिन साल 2012 में देश के आम आदमी ने उठकर अपनी खुद की पार्टी 'आम आदमी पार्टी' की स्थापना की थी। तब से लेकर आज तक इन 11 साल में बहुत उतार-चढ़ाव आए, बहुत मुश्किलें भी आई, लेकिन हम सबके जज्बे और जुनून में कोई कमी नहीं आई है। एक छोटी सी पार्टी को आज जनता ने अपने प्यार और आशीर्वाद से एक राष्ट्रीय पार्टी में बदल दिया है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, हम सब अपने मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और जनता के लिए काम करते रहेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

2013 में लिया पहला चुनाव लड़ने का फैसला

बता दें कि सिस्टम से भ्रष्टाचार खत्म करने और वैकल्पिक राजनीति का मॉडल सामने रखने के वादे के साथ आम आदमी पार्टी ने धमाकेदार एंट्री की थी। आम आदमी पार्टी ने दिसंबर, 2013 में दिल्ली विधानसभा का अपना पहला चुनाव लड़ने का फैसला किया था। वर्ष 2012 में आम आदमी पार्टी ने देश में चुनावी चंदा जुटाने के भीड़-स्रोत मॉडल की शुरुआत की, जिसमें छोटे दान के साथ पार्टी शुरू से ही चल रही थी।

बिजली-पानी आंदोलन

आम आदमी पार्टी ने अपना पहला दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले जो पहला मुद्दा उठाया था, वह बिजली की दरों और पानी के बिलों को फर्जी तरीके से बढ़ाए जाने का था। आप ने वर्ष 2013 में बिजली वितरण कंपनियों और पानी टैंकर माफिया के साथ मिलीभगत के खिलाफ सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था।

23 मार्च से अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित सरकार पर दबाव बनाने के लिए अनशन शुरू कर दिया था। इसके साथ ही, पार्टी ने इस उद्देश्य के लिए समर्थन संगठित करने के लिए एक बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर अभियान चलाया था। पार्टी द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को दिल्ली के लोगों की 10.5 लाख से अधिक याचिकाएं सौंपने के 14वें दिन केजरीवाल ने अपना उपवास तोड़ा। इस आंदोलन ने आप को एक राजनीतिक ताकत बना दिया।

AAP को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का मिला दर्जा

आम आदमी पार्टी (आप) देश की एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। चुनाव आयोग की ओर से अप्रैल महीने में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। वर्षी 2022 में गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए करीब 12 प्रतिशत वोट हासिल किए थे। आप की दिल्ली और पंजाब दो राज्यों में सरकार और दिल्ली एमसीडी में पहली बार पार्टी ने अपना मेयर बनाया है।

एंटी स्मॉग गन की क्षमता हुई दोगुनी, अब तीन घंटे तक लगातार हो सकेगा छिड़काव

एनडीएमसी के अधिकारी ने बताया कि 17 हजार लीटर पानी की क्षमता होने के साथ वाहन पर लगी एंटी स्मॉग गन 45 डिग्री तक ऊपर व नीचे की ओर 220 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। इससे फुटपाथ के साथ झाड़ियों के साथ ही अन्य स्थानों को धोने में भी मदद मिलेगी। इससे अब तीन घंटे तक लगातार पानी का छिड़काव हो सकेगा।

नई दिल्ली। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए पानी के छिड़काव में एंटी स्मॉग गन से छिड़काव किया जाता है, लेकिन दस हजार लीटर पानी की क्षमता होने की वजह से इसे एक से डेढ़ घंटे बाद पुनः भरना पड़ता है।

इसे देखते हुए एनडीएमसी ने 17 हजार लीटर की क्षमता वाली टैंक के साथ एक एंटी स्मॉग गन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अपने बेड़े में शामिल की है। इससे अब तीन घंटे तक लगातार पानी का छिड़काव हो सकेगा।

एनडीएमसी के अनुसार पानी की टंकी क्षमता 17 हजार लीटर होने से जो इसके भरने और फिर पुनः छिड़काव प्वाइंट पर लौटने में समय लगता था वह भी कम हो जाएगा।

अब 17 हजार लीटर की लगाई है मशीन

एनडीएमसी के अधिकारी ने बताया कि 17 हजार लीटर पानी की क्षमता होने के साथ वाहन पर लगी एंटी स्मॉग गन 45 डिग्री तक ऊपर व नीचे की ओर 220 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। इससे फुटपाथ के साथ, झाड़ियों के साथ ही अन्य स्थानों को धोने में भी मदद मिलेगी।

इसके नोजल से अब 30 से 50 मीटर तक पानी फेंका जा सकता है। चार से पांच कर्मियों द्वारा दो शिफ्ट में यह एंटी स्मॉग गन प्रतिदिन औसतन 70 किलोमीटर क्षेत्र में पानी का छिड़काव कर सकेगी। एनडीएमसी के पास 5 से दस हजार क्षमता वाले 18 पानी के टेंकर और ट्राली पहले से ही तैनात है।

एक महीने से गैस चैंबर में जीने को मजबूर दिल्ली के लोग, NCR की हवा भी सांस लेने लायक नहीं; AQI 500 पार

प्रतिदिन दो से तीन बार यह वाहन पानी का छिड़काव एनडीएमसी इलाके में कर रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्मॉग गन चलेगी। अगर, इसके परिणाम और उपयोग सही व संतोषजनक पाया जाता है तो इसकी संख्या को बढ़ाया जाएगा।

कदम-कदम पर बैठे धोखेबाज, संपत्ति खरीदें जरा संभलकर

परिवहन विशेष न्यूज

अगर आप कोई संपत्ति खरीद रहे हैं तो सबसे पहले जहां पर जमीन है वहां के आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ कर लें। जिससे जमीन खरीद रहे हैं उसके बारे में पता कर लें। साथ ही अगर संबंधित व्यक्ति ने पहले किसी अन्य जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचा है तो उससे भी पूछताछ कर लें। तहसील में जाकर कागज के बारे में वेरीफिकेशन करना बेहतर रहेगा।

गुरुग्राम। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले साइबर ठगी के आते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर प्लाट, जमीन और मकान की खरीद के नाम पर धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं।

ओएलएक्स व अन्य इंटरनेट मीडिया के माध्यम से विज्ञापन डालकर कुछ लोग संपत्ति खरीदने वाले व्यक्तियों के साथ आसानी से धोखाधड़ी कर रहे हैं। जमीन की धोखाधड़ी से संबंधित मामलों का कई बार पुलिस भी संज्ञान नहीं लेती। थानों में दर्ज हुए ज्यादातर मामले ऐसे हैं, जो कोर्ट के संज्ञान में लाने के बाद दर्ज किए गए हैं।

बीते छह महीनों में गुरुग्राम के विभिन्न थानों में संपत्ति धोखाधड़ी से संबंधित 30 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इन सभी में एक बात सामान्य रूप से आई है कि आरोपितों ने किसी न किसी माध्यम से लोगों को फंसाया और संपत्ति बेचकर रकम हड़प ली।

कई मामले ऐसे भी आए, जब आरोपितों ने एक बार बेची हुई संपत्ति की दोबारा रजिस्ट्री करा दी। ऐसे मामलों की तह तक जाने पर कई बड़े नाम की भी संलिप्तता पाई जा सकती है। यह एक तरीके का संगठित अपराध है। इसमें कोई अकेला व्यक्ति ठगी नहीं करता, कई लोग मिलकर अपराध में शामिल होकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं।

दो महीने पहले ही पकड़ा था रजिस्ट्री का बड़ा फर्जीवाड़ा

दो महीने पहले ही गुरुग्राम पुलिस ने फर्जी जीपीए के आधार पर एनआरआइ की 40 करोड़ की 15 कनाल जमीन को छह करोड़ में दिखाकर रजिस्ट्री कराने में शामिल गिरोह का भंडाफोड़ किया गया था।

पुलिस ने फर्जी जीपीए बनाने में मददगार रहे दिल्ली के कालकाजी तहसील के कर्मचारी, आर्थिक अपराध शाखा में तैनात एएसअइ समेत पांच को गिरफ्तार किया था।

इस मामले में एक मार्च 2022 को पूर्ण मनचंदा नाम के व्यक्ति ने पुलिस आयुक्त को लिखित शिकायत देकर कुछ व्यक्तियों पर गांव बेगमपुर खटोला में उनकी जमीन को जाली व फर्जी कागजात के आधार पर पंजीकृत कराकर हड़पने का आरोप लगाया था।

केस एक

दौलताबाद के बाबूपुर निवासी राहुल यादव ने अगस्त 2022 में हरसरु में साढ़राणा के पास राजकुमार नाम के व्यक्ति से 1115 वर्गगज की जमीन खरीदी। जब राहुल प्लाट पर चारदीवारी बना रहे थे तो कुछ लोग आए और अपना प्लाट बताकर चारदीवारी तोड़ दी।

जब राहुल ने इस बारे में राजकुमार को बताया तो उसने अपनी गलती स्वीकार की। शिकायत करने पर पुलिस आयुक्त के आदेश के बाद बीते सप्ताह सेक्टर 10 थाना पुलिस ने केस दर्ज किया।

केस दो

झाड़सा गांव निवासी 65 वर्षीय केशरी देवी के साथ कुछ लोगों ने प्रापर्टी बेचने के नाम पर सवा करोड़ की धोखाधड़ी कर ली। कोर्ट के आदेश पर सेक्टर 40 में एक सप्ताह पहले दस नामजद आरोपितों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।

इसमें शपथ पत्र बनाने, पास करने और गवाह के रूप में हस्ताक्षर करने वाले भी शामिल थे। केशरी देवी ने कोर्ट में दी शिकायत में बताया था कि उन्होंने प्रापर्टी डीलर के माध्यम से अप्रैल 2023 में सेक्टर 40 स्थित ग्रीनवुड सिटी में तीन मंजिल का मकान खरीदा था। उन्होंने इसके लिए एक करोड़ 24 लाख रुपये दिए थे।

केस तीन

दिल्ली के पालम विहार निवासी ज्योति से एक व्यक्ति ने प्लाट बेचने के नाम पर छह लाख रुपये ठग लिए।आरोप लगाया कि शमशेर सिंह नाम के व्यक्ति ने उन्हें प्लाट दिखाया और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर उन्हें छह लाख रुपये प्लाट बेच दिया।

प्लाट पर कब्जा नहीं मिला तो जांच करने पर महिला को पता चला कि वह प्लाट किसी दूसरे व्यक्ति का है और उसके साथ ठगी की गई है। दस नवंबर को इस धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज हुआ है।

केस चार

भारतीय सेना में तैनात सौ से ज्यादा रक्षा कर्मियों व सेवानिवृत्त कर्मियों के संगठन रक्षक वेलफेयर हाउसिंग सोसायटी की करोड़ों की जमीन हड़प ली गई। संगठन ने इस मामले में एक व्यक्ति के माध्यम से पौने तीन एकड़ जमीन मानेसर के गांव सीही में घर बनाने के लिए ली थी।

आरोपित ने धोखे से दो हजार गज जमीन अपने नाम करा ली थी। पुलिस आयुक्त से शिकायत के बाद 12 अक्टूबर को खेड़कीदौला थाने में केस दर्ज हुआ।

यह एक संगठित अपराध है, इसमें कई लोगों का गिरोह काम करता है। कहीं ना कहीं इसमें कुछ रसूखदार भी शामिल होते हैं। ऐसे मामलों में कार्रवाई करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। वहीं अगर पुलिस ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं करती है, तो पीड़ित व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। वहां से उसे न्याय जरूर मिलेगा।

एडवोकेट ममता कालरा

अगर आप कोई संपत्ति खरीद रहे हैं तो सबसे पहले जहां पर जमीन है, वहां के आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ कर लें। जिससे जमीन खरीद रहे हैं, उसके बारे में पता कर लें। साथ ही अगर संबंधित व्यक्ति ने पहले किसी अन्य जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचा है तो उससे भी पूछताछ कर लें। तहसील में जाकर कागज के बारे में भी वेरीफिकेशन करना बेहतर रहेगा। इससे ठगे जाने से बचाव होगा।

यमुना एक्सप्रेसवे पर मिली शिवा ढाबा से चोरी हुई कार, जांच में जुटी पुलिस

ग्रेटर नोएडा के शिवा ढाबा से ज्वेलरी समेत चोरी हुई कार संदिग्ध परिस्थिति में यमुना एक्सप्रेसवे पर मिली है। जौनपुर के रहने वाले आभूषण व्यापारी की शिवा ढाबा के सामने से कार चोरी हुई थी। कार में एक बैग रखा था। बैग में ज्वेलरी थी। मामले में जौनपुर के रहने वाले आभूषण व्यापारी गणेश सोनी की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है।

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के शिवा ढाबा से ज्वेलरी समेत चोरी हुई कार संदिग्ध परिस्थिति में यमुना एक्सप्रेसवे पर मिली है। जौनपुर के रहने वाले आभूषण व्यापारी की शिवा ढाबा के सामने से कार चोरी हुई थी। कार में एक बैग रखा था। बैग में ज्वेलरी थी।

पीड़ित का आरोप है कि उनकी कार ज्वेलरी समेत चोरी हुई। संदिग्ध परिस्थितियों में चोरी हुई कार आज रविवार को जीरो पॉइंट से 44 किलोमीटर पर अलीगढ़ क्षेत्र में मिली है। मामले में जौनपुर के रहने वाले आभूषण व्यापारी गणेश सोनी की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है।

चालक को बंधक बनाकर लूटने वाले चार बदमाशों को लगी गोली

दादरी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत दो दिन पहले चालक को बंधक बनाकर सीमेंट के कट्टे से भरा ट्रैक्टर ट्राली लूटने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। चार बदमाशों को मुठभेड़ में गोली लगी है। चारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों के कब्जे से लूटा गया ट्रैक्टर ट्राली, 320 सीमेंट के कट्टे, होंडा सिटी कार, तमंचा व कारतसू बरामद किया गया है।

एडिशनल डीसीपी ग्रेटर नोएडा अशोक कुमार ने बताया कि दादरी के अयोध्या गंज में रहने वाले महेंद्र कुमार सीमेंट सप्लाई का काम करते है। 23 नवंबर की सुबह उनका चालक सुदेश रोज की तरह सिकंदराबाद सीमेंट का कट्टा लेने गया था। ट्रैक्टर ट्राली में 320 सीमेंट के कट्टे लोड कर वह वापस दादरी के लिए आ रहा था। जैसे ही वह लुहारली टोल प्लाजा के समीप पहुंचा तभी होंडा सिटी कार में सवार होकर आए बदमाशों ने चालक सुदेश को गन प्वाइंट पर रोक लिया। उससे सीमेंट से भरा हुआ ट्रैक्टर लूट लिया था। शनिवार को दादरी कोतवाली प्रभारी सुजीत उपाध्याय की टीम ने चारों बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में धर दबोचा। आरोपितों की पहचान विजय कुमार, विष्णु शर्मा, पिंटू शर्मा व विनोद के रूप में हुई है। विजय जारचा का रहने वाला है जबकि अन्य तीनों बुलंदशहर के रहने वाले है।

पंजाब में बेचने की फिराक में थे एसीपी दादरी सार्थक सेंगर ने बताया कि पकड़े गए आरोपित लूट की सीमेंट को पंजाब में बेचने वाले थे।

विवाह मंडप में लगी आग, दमकल की पांच गाड़ियों ने पाया आग पर काबू

पांडव नगर स्थित मार्शल महल विवाह मंडप में आग लगी। रात करीब 3 बजे की घटना है। आग फाइबर शीट्स में लगी। कुछ ही देर में परिसर में फैल गयी। दमकल की पांच गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। परिसर में देर रात रिपेयरिंग का काम चल रहा था। सीएफओ का कहना है कि आग विवाह मंडप के एक बंद कमरे से शुरू हुई।

गाजियाबाद। पांडव नगर स्थित मार्शल महल विवाह मंडप में शनिवार देर रात करीब साढ़े तीन बजे आग लग गई। आग फाइबर शीट्स में लगी और कुछ ही देर में परिसर में फैल गयी।

दमकल की पांच गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। परिसर में देर रात रिपेयरिंग का काम चल रहा था। सीएफओ राहुल पाल का कहना है कि आग विवाह मंडप के एक बंद कमरे से शुरू हुई। कुछ देर में ही आग मंडप परिसर में लगी फाइबर शीट तक पहुंच गई।

एसएफओ कोतवाली शेषनाथ यादव का कहना है कि शुरुआती जांच में आग की वजह शार्ट सर्किट लग रहा है। विवाह मंडप के मालिक इंद्रपाल निवासी काजीपुरा हैं। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है।

155 आइपीएस अधिकारियों ने लिया आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण

कमला नेहरु नगर स्थित एनडीआरएफ की आठवीं बटालियन में शनिवार को सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में प्रशिक्षण ले रहे 75 आरआर बैच के 155 आइपीएस आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण लिया। एनडीआरएफ डीआइजी भारत भूषण, एवं एनडीआरएफ वाहिनी के द्वितीय कमान नीरज कुमार ठाकुर आईपीएस अधिकारी दल का स्वागत किया।

भारत भूषण ने एनडीआरएफ की कार्यप्रणाली, डिजास्टर मेनेजमेंट, इंसिडेन्ट रिस्पोंस सिस्टम एवं आपदाओं के दौरान पुलिस का रोल एवं सिविल अथोरिटी के साथ समन्वय पर प्रजेंटेशन दिया गया। इसके बाद सीबीआरएन आपदा, बाढ़ एवं भूकंप के दौरान इस्तेमाल होने वाले अत्याधुनिक उपकरणों भी दिखाए।

उप सेनानी कुणाल तिवारी ने हजमत व्हीकल के बारे में जानकारी दी। उप सेनानी दीपक तलवार एनडीआरएफ की विषेशज्ञ टीम द्वारा भूकंप आने पर ध्वस्त संरचनाओं तथा उंची इमारतो में फंसे लोगो को बचाने के तरीकों पर आधारित प्रर्दशन दिखाया गया। इसके अलावा कुत्तों द्वारा खोज प्रदर्शन, केमिकल एवं जहरीली गैस का रिसाव होने पर किये जाने वाले राहत कार्य बारे में जानकारी दी गई।

हवा 'जहरीली' होने के ये हैं मुख्य कारण

दिल्ली के साथ देश में पांचवां सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद

परिवहन विशेष न्यूज

देश के 244 शहरों में शनिवार को दिल्ली के साथ गाजियाबाद पांचवां सबसे प्रदूषित शहर रहा। दिल्ली व गाजियाबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 389 दर्ज किया गया। वहीं सबसे प्रदूषित हवा हनुमानगढ़ की दर्ज की गई। जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक 401 के साथ शुक्रवार को गंभीर श्रेणी में पहुंच गया था। लोनी की हवा जिले में सबसे खराब दर्ज की गई।

गाजियाबाद। देश के 244 शहरों में शनिवार को दिल्ली के साथ गाजियाबाद पांचवां सबसे प्रदूषित शहर रहा। दिल्ली व गाजियाबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 389 दर्ज किया गया। वहीं सबसे प्रदूषित हवा हनुमानगढ़ की दर्ज की गई।

जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक 401 के साथ शुक्रवार को गंभीर श्रेणी में पहुंच गया था। शनिवार को एक्यूआइ कम होकर गंभीर से बेहद खराब श्रेणी में आ गया है। जिले का एक्यूआइ कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी दिल्ली के साथ देश में पांचवां सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है।

जिले में सबसे खराब लोनी की हवा

लोनी की हवा जिले में सबसे खराब दर्ज की गई। स्माग से लोगों की आंखों में जलन, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत समेत विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ा। इससे अस्पतालों में भी मरीज बढ़ रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है।

समय रहते प्रदूषण रोकथाम के इंतजाम किए जाते तो यह स्थिति नहीं आती। जिले में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के चौथे चरण की पाबंदियां लागू जरूर हैं, लेकिन जिले के अधिकारी न तो इनका खुद पालन कर रहे हैं और न ही प्रदूषण फैलाने वालों से करा पा रहे हैं।

सुबह में गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया था AQI

जिले की हवा शनिवार सुबह बजे गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई थी। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 424 दर्ज किया गया था। इंदिरापुरम की हवा जिले में सबसे खराब दर्ज की गई। एक्यूआइ 450 पहुंच गया था। दोपहर चार बजे तक इसमें बदलाव हो गया। जिले की हवा गंभीर से बेहद खराब व लोनी की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई।

प्रदूषण बढ़ने के ये हैं मुख्य कारण

छिड़काव न होने से सड़कों पर उड़ रही धूल

उम्र पूरी कर चुके वाहनों का संचालन होना

औद्योगिक क्षेत्रों में चिमनियों से निकलता धुआं

रोक के बाद भी निर्माण कार्य होना

कूड़े में आग जलाने पर रोक न लगना

शनिवार को देश के सबसे प्रदूषित शहर

शहर	AQI
हनुमानगढ़	447
फरीदाबाद	416
बेगुसराय	411
धोलपुर	396
दिल्ली	389
गाजियाबाद	389

स्टेशनों का एक्यूआइ

स्टेशन	एक्यूआइ
वसुंधरा -	390
इंदिरापुरम -	370
संजय नगर -	375
लोनी -	421

जिले का एक्यूआइ

24 नवंबर - 401
23 नवंबर - 361
22 नवंबर - 344
21 नवंबर - 346
20 नवंबर - 321

हम अपने स्तर से प्रदूषण रोकने की लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जिन क्षेत्रों में अधिक प्रदूषण की समस्या है वहां प्राथमिकता से काम किया जा रहा है। प्रदूषण फैलाने पर जुर्माना लगाया जा रहा है।

-विकास मिश्र, क्षेत्रीय अधिकारी, यूपीपीसीबी।

विश्व की सुंदरतम नगरी बनने और वैश्विक पटन पर छाने के लिए तैयार है अयोध्या

मृत्युंजय दीक्षित

अयोध्या में विकास की गति को और तीव्र करने के लिए नौ नवंबर 2023 को अयोध्या में रामलला के दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसने एक नया इतिहास रचा।

500 वर्षों के अथक संघर्ष के पश्चात नौ नवंबर 2020 को माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा अयोध्या पर राम मंदिर के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय देने के बाद, श्रीराम जन्मभूमि पर श्री रामलला के भव्य–दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य तीव्र गति से सम्पूर्णता की दिशा में अग्रसर है। मंदिर के भूतल का लगभग 95 प्रतिशत का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा आगामी 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होना भी सुनिश्चित हो गया है।

कुछ वर्ष पूर्व तक जो अयोध्या नगरी हिन्दुओं के संघर्ष की धरती थी जो आगामी 22 जनवरी 2024 को सर्व संतोषकारिणी नगरी बनने जा रही है। लंबे संघर्ष के बाद प्रभु श्रीराम लला अपने जन्मभूमि आवास में पधार रहे हैं और प्रत्येक सनातनी यह सोचकर हर्षित और प्रफुल्लित हो रहा है कि अयोध्या में श्रीरामलला के विराजमान हो जाने के बाद उनके सभी दुखों व चिंता का निवारण हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं संपूर्ण भारत में आनंद की बयार बह रही है और हो भी क्यों न हम सबके श्रीराम अपने घर आ रहे हैं। यही कारण है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार अयोध्या को अखिल विश्व की सुंदरतम नगरी बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है।

एक समय था जब रामभक्त अयोध्या दर्शन करने जाते अवश्य थे किंतु हनुमानगढ़ी और कनक भवन के दर्शनों तक सीमित रह जाते थे और बहुत कम श्रद्धालु श्री रामजन्मभूमि के दर्शन करने के लिए जाते थे क्योंकि तम्बू में बैठे भगवान तक पहुंचना सरल नहीं था किन्तु उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने के बाद परिवर्तन आया और 22 जनवरी 2024 के बाद परिस्थितियां पूरी तरह से बदलने जा रही हैं क्योंकि अब रामभक्तों व श्रद्धालुओं की प्रतीक्षा पूर्ण और धैर्य समाप्त हो रहा है।

भव्य श्रीरामलला मंदिर के उद्घाटन के पश्चात श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने वाली है, अयोध्या में उनके भव्य स्वागत, रहने-ठहरने व दिव्य दर्शन सुलभ करने के लिए व्यापक प्रबंध किये जा रहे हैं। अयोध्या व उसके आसपास के समस्त क्षेत्र को इस प्रकार से निर्मित किया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को त्रेतायुग के समय का आभास हो और उस परिकल्पना को साकार करने के लिए मुख्यंमत्री योगी आदित्यनाथ जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तभी से जुटे हैं। विगत कई वर्षों से अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयेजन किया जा

रहा है जिसमें प्रभु श्रीराम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उसी प्रकार पुष्पक विमान से उतरते हैं जिस प्रकार वह त्रेता युग में उतरे थे। अयोध्या त्रेतायुग में जिस प्रकार प्रफुल्लित व हर्षित हुई थी आगामी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या व उसके आसपास के वातावरण को उसी प्रकार राममय करने की अभूतपूर्व तैयारी चल रही है।

इसी परिप्रेक्ष्य में अयोध्या को विश्व की सुंदरतम नगरी बनाने के लिए हर संभव व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। 22 जनवरी के बाद देश व विदेशों से लाखों की संख्या में रामभक्त अयोध्या पहुंचने वाले हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए और अयोध्या को विश्व स्तर की धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करने के लिए करीब 3 हजार करोड़ रुपए लागत की विभिन्न अवस्थापना परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के नाम पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि आगामी दिसंबर माह में उड़ानें भी प्रारंभ हो जायेंगी। वंदे भारत ट्रेन लखनऊ से अयोध्या के बीच चली है और करीब आधा दर्जन अन्य रेल गाड़ियाँ अयोध्या से होकर जाने लगी हैं। अयोध्या से रामेश्वरम तक सीधी रेलगाड़ी चलाई गई है।

अयोध्या का बदलाव दिखाने के लिए रेलवे स्टेशन को भव्य बनाया जा रहा है। पर्यटन विभाग अयोध्या को जोड़ने वाले सुल्तानपुर, बस्ती, गोंडा, अंबेडकरनगर और रायबरेली हाईवे पर बड़े द्वारों का निर्माण कर रहा है। अयोध्या व आसपास के जिलों व कस्बों में भारी संख्या में होटलों आदि का निर्माण कार्य चल रहा है। तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं-अयोध्या में बाहर आने वाले तीर्थयात्री केवल अयोध्या मंदिर दर्शन तक ही सीमित न रह जाएं इसलिए तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं पर भी कार्य चल रहा है। पंचकोसी, चौदह कोसी तथा चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग पर स्थित धार्मिक स्थलों का भी सुंदरीकरण किया जा रहा है। सरयू नदी में विहार के साथ मंदिरों के दर्शन के लिए क्रूज सेवा और रोमांचक वाटर स्पोर्टस सेवा भी प्रारंभ हो गई है। साथ ही अभी कई और योजनाएं प्रारंभ होने वाली हैं।

भविष्य की दृष्टि से अयोध्या का दिव्य एवं नव्य विकास करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संकल्पवान हैं। मुख्यमंत्री का दायित्व सँभालने के साथ से ही वे अयोध्या पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और प्रायः अयोध्या आकर सांधु-संतों का आशीर्वाद के लेने के साथ ही साथ विकास हेतु उनका परामर्श भी लेते हैं। 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी जी अपने प्रथम कार्यकाल में 46 बार अयोध्या पहुंचे और इस कार्यकाल में भी उनका आगमन निरंतर हो रहा है। वो अयोध्या सम्बन्धी प्रत्येक कार्य पर स्वयं दृष्टि रखते हैं। योगी जी के नेतृत्व में अयोध्या में हर वर्ष दीपोत्सव का आयोजन होने से अयोध्या को एक नयी पहचान मिली है। हर वर्ष दीपों की संख्या गिनीज़ बुक में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व इस बार भी अयोध्या में अयोजित भव्य दीपोत्सव ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और अयोध्या की अनुपम छटा बिखर रही है।

अयोध्या में विकास की गति को और तीव्र करने के लिए नौ नवंबर 2023 को अयोध्या में रामलला के दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसने एक नया इतिहास रचा। कैबिनेट बैठक के पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रदेश सरकार के सभी मंत्री रामलला के दरबार पहुंचे और उनके प्रति अपनी आस्था प्रकट की। कैबिनेट ने हनुमानगढ़ी में भी हनुमान जी के दर्शन किये और पूजा की। हनुमानगढ़ी में महंत धर्मदास, महंत संतरामदस आदि ने सभी अभिनंदन किया और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अप सभी के आशीर्वाद से अयोध्या विश्व की सबसे सुंदरतम नगरी बनेगी।

अयोध्या तीर्थ विकास परिषद का गठन

अयोध्या में आयोजित बैठक में अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद व देवी पाटन धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन को स्वीकृति दी गयी। अयोध्या कैबिनेट में शुक्त तीर्थक्षेत्र विकास परिषद के गठन का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। ज्ञातव्य है कि अयोध्या के समग्र विकास के लिए पहले से ही केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से 30,500 करोड़ रुपये की कुल 178 परियोजनाएँ चल रही हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि अयोध्या के समग्र विकास के लिए अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के गठन का निर्णय लिया गया है। यहां आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को उच्च स्तरीय पर्यटन सुविधाओं के विकास के साथ ही परंपरा और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए आवश्यक नीतियां

लग्जरी गाड़ियों की बढ़ी डिमांड, Mercedes, Audi की इस फेस्टिव सीजन में हुई बंपर बिक्री

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए मर्सिडीज-बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक संतोष अय्यर ने कहा कि कई नए लॉन्च आकर्षक पोर्टफोलियो और मजबूत ग्राहक भावना के कारण इस साल ओणम से दिवाली तक त्योहारी सीजन पिछले साल की तुलना में बेहतर रहा है। ऑडी इंडिया चीफ बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि जनवरी-सितंबर 2023 में 5530 इकाइयों की खुदरा बिक्री के साथ 88 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

नई दिल्ली। देश में लग्जरी कारों की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है। इस बात का अंदाजा आप फेस्टिव सीजन में हुई बिक्री से लगा सकते है। जानकारी के लिए बता दें, लग्जरी कार निर्माण करने वाली कंपनी मर्सिडीज और ऑडी ने इस फेस्टिव सीजन जमकर गाड़ियों की बिक्री की है।

ऑडी सेल्स रिपोर्ट

ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि कंपनी ने जनवरी-सितंबर 2023 में 5,530 इकाइयों की खुदरा बिक्री के साथ 88 प्रतिशत की वृद्धि देखी है। जोकि पिछले साल के कंपैरिजन में काफी बेहतर है। ढिल्लन ने कहा कि इस साल भारत में लक्जरी कार उद्योग 2018 की मात्रा को पार कर गया है, जहां 2018 में 46 हजार गाड़ियों की बिक्री हुई थी, वहीं इस साल ये संख्या बढ़कर 47,000 यूनिट के आंकड़े तक पहुंच जाएगा।

मर्सिडीज-बेंज

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए मर्सिडीज-बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक संतोष अय्यर ने कहा कि कई नए लॉन्च, आकर्षक पोर्टफोलियो और मजबूत ग्राहक भावना के कारण इस साल ओणम से दिवाली तक त्योहारी सीजन पिछले साल की तुलना में बेहतर रहा है।

ऑटो इंडस्ट्री इस साल रिकॉर्ड बिक्री की उम्मीद कर रही है, जहां फिलहाल अभी पॉजिटिव शाइन दिख रहा है। हालांकि, सप्लाई चेन की कमी अभी भी बरकरार है। मंथली सेल्स रिपोर्ट की बात करें तो लग्जरी कारों की बिक्री में पहले पॉजिशन पर मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू की कारें होती हैं।

जुलाई महीने BMW ने 1,097 इकाइयों की बिक्री की है, जो पिछले साल समान अवधि में बेची गई 932 इकाइयों से अधिक है। वहीं जुलाई महीने मर्सिडीज-बेंज ने 1,019 इकाइयों की बिक्री की है, जो पिछले साल समान अवधि में बेची गई 1,067 यूनिट से कम है।

सिंगल चार्ज में तगड़ा रेंज देते हैं ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, कीमत है मात्र इतनी

हम आपके लिए ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आए हैं जो एक बार में ही आपको सिंगल चार्ज में 150 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी।

नई दिल्ली : इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते समय लोगों के मन में यह सवाल जरूर रहता है कि कहीं यह बीच में धोखा ना दे जाए, जो की एक जायज सवाल है।

दरअसल पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक स्कूटर इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है. ऐसे में अब जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में मौजूद है उन सभी में इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि एक अच्छी रेंज इनमें ऑफर की जाए साथ ही इनमें दमदार फीचर्स भी हो जिनकी बदौलत आप मजे से लंबा सफर कर पाएं। आज हम आपके लिए ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आए हैं जो एक बार में ही आपको सिंगल चार्ज में 150 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी।

एथर 450X (रेंज: 146 किमी)

Best Range E-Scooter : एथर 450X भारत के प्रमुख ईवी स्टार्टअप्स में से एक की ओर से पेश किया जाने वाला एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर है। यह ईवी एक बार चार्ज करने पर 146 किमी की रेंज देने का दावा करती है, जो स्कूटर में लगे 3.7kWh बैटरी पैक से आता है। इस बैटरी पैक को PMS मोटर से जोड़ा गया है जो 6.5kW का अधिकतम पावर आउटपुट और 26Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। यह पावरट्रेन एथर 450X को 90 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक जाने में भी मदद करता है। बैटरी पैक को घरेलू चार्जर से 5 घंटे 40 मिनट में शून्य से 100 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है। एथर 450X में डिस्क ब्रेक, 22 लीटर का बूट स्पेस, ऑटो होल्ड, 12 इंच के अलॉय व्हील, राइडिंग मोड और आईपी सर्टिफिकेशन भी शामिल हैं। एथर 450X कंपनी के एथरस्टैक सॉफ्टवेयर के साथ एक आजमाया हुआ और परीक्षण किया हुआ 7-इंच टीएफटी कलर टचस्क्रीन भी प्रदान करता है जो स्कूटर से जुड़े वाहन सुविधाएँ प्रदान करता है।

Best Range E-Scooter : टीवीएस आईक्यूब एसटी टीवीएस की सबसे सुसज्जित ईवी पेशकश है और एक बार चार्ज करने पर 145 किमी की रेंज देने का वादा करती है। चार्ज को ऑनबोर्ड 4.56kWh ली-आयन IP67 बैटरी पैक में संग्रहीत किया जाता है, जिसे 950W चार्जर के माध्यम से शून्य से 80 प्रतिशत तक चार्ज होने में लगभग 4 घंटे और 6 मिनट का समय लगता है। स्कूटर में एलईडी लाइटिंग, एक प्रैक्टिकल फ्लोरबोर्ड, डिस्क ब्रेक, आरामदायक सस्पेंशन, 12-इंच अलॉय व्हील, कनेक्टेड तकनीक, 7-इंच टचस्क्रीन आदि जैसे फीचर्स मिलते हैं।

घर बैठे मिनटों में भरे ऑनलाइन चालान, बस फॉलो करें ये आसान टिप्स

अगर कोई भी व्यक्ति ड्राइव करते समय नियमों को तोड़ता है तो उसे चालान भरना पड़ता है। अगर आपके वाहन का भी चालान कट गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसे ऑनलाइन भर सकते हैं। बस आपको इसके लिए पहले ई-चालान पोर्टल पर जाएं।अगर आपका भी चालान कटा है तो आप घर बैठे ही चालान को भर कर सकते हैं।

नई दिल्ली। भारत में सड़क दुर्घटना की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। इस की वजह से हर साल लाखों लोगों की जान चली जाती है। जिसके कारण सरकार ने सड़क पर वाहन चलाने के लिए कई नियम बनाए हैं। ताकि यातायात नियमों का सही से पालन हो सके। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने अब ऑनलाइन चालान का ऑनलाइन चालान की व्यवस्था भी कर दी है।

घर बैठे ही चालान को भरें

अगर कोई भी व्यक्ति ड्राइव करते समय नियमों को तोड़ता है तो उसे चालान भरना पड़ता है। अगर ट्रैफिक पुलिस ने चालान जारी कर दिया तो आपको चालान भरना ही पड़ेगा। रोड एक्सिडेंट की बढ़ती संख्या के कारण, चालान काटा जाता है। ताकि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अगर आपका भी चालान कटा है तो आप घर बैठे ही चालान को भर कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको कुछ जरुरी स्टेप्स को फॉलो करना होगा। चलिए आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी देते हैं।

इन स्टेप्स को फॉलो करें

अगर आपके वाहन का भी चालान कट गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसे ऑनलाइन भर सकते हैं। बस आपको इसके लिए पहले ई-चालान पोर्टल पर जाएं। इसके बाद आपको होम पेज पर चालान नंबर, वाहन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर का ऑप्शन मिलेगा, जिनमें से किसी एक का चयन पर उसकी डिटेल भर दें। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें चालान का विवरण आपके सामने खुल जाएंगा। इसके बाद अभी भुगतान करें पर क्लिक करें।

भुगतान होने के बाद मिलेगी रसीद

इसके बाद, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI से पेटीएम करके आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसमें बाद आपके फोन पर मैसेज आ जाएगा। इसके कारण आपका समय बचेगा और आप समय पर भी चालान भर सकते हैं।

2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में आ सकती है 5 डोर इलेक्ट्रिक थार, जानें इसमें क्या कुछ होगा खास

इस इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत लगभग 18 .5 लाख रुपये के बीच हो सकती है। इसके साथ ही बढ़ी हुई ग्राउंड क्लीयरेंस के कारण ऑफ रोड पर गाड़ी को चलाने में काफी मदद मिलेगी।आने वाली इलेक्ट्रिक थार 5 डोर में 60kWh की बैटरी पैक मिल सकती है। कंपनी बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म (INGLO-P1 EV) पर तैयार करेगी।कंपनी 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में इसका इलेक्ट्रिक वर्जन उतारेगी।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में महिंद्रा अपनी एसयूवी के लिए जानी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एसयूवी थार का 5 डोर मॉडल अगले साल लॉन्च के लिए तैयार है। इसके बाद कंपनी 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में इसका इलेक्ट्रिक वर्जन उतारेगी। इसका डिजाइन अगस्त में दक्षिण अफ्रीका में पेश किए गए थार इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट के समान ही होगा। कंपनी बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म (INGLO-P1 EV) पर तैयार करेगी।

कॉन्सेप्ट से मिलता-जुलता होगा डिजाइन

आने वाली 5 डोर इलेक्ट्रिक थार में चौकोर फेंडर, चौकोर हेडलैंप,3 LED स्लैट एलिमेंट्स के साथ इसका लुक काफी शानदार है। इसके केबिन में ग्रैब हैंडल के साथ फ्लैट डैश, कैपेसिटिव कंट्रोल के साथ 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर लाइव स्टेटस पिक्टोग्राम भी मिलता है। इसको डिजाइन कुछ इस तरह से किया गया है जिससे इसका लुक अच्छा लगा। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी के अंदर एक पानी की नली होगी, जो ऑफ-रोडिंग के बाद केबिन को पूरी तरह से साफ कर सकती है।

325 किलोमीटर से ज्यादा की देगी रेंज

आने वाली इलेक्ट्रिक थार 5 डोर में 60kWh की बैटरी पैक मिल सकती है। जिसे एक बार चार्ज करने पर 325 किलोमीटर से भी अधिक का रेंज मिल सकती है। यह फॉक्सवैगन की पावरफुल की मोटर से लैस होगी। इसका व्हीलबेस 2,775mm से 2,975mm के बीच हो सकता है।

इस इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत लगभग 18.5 लाख रुपये के बीच हो सकती है। इसके साथ ही बढ़ी हुई ग्राउंड क्लीयरेंस के कारण ऑफ रोड पर गाड़ी को चलाने में काफी मदद मिलेगी।आपकी जानकारी के लिए बता दें, कंपनी ने इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

भारत के प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने वाले राजनेताओं ने

ललित गर्ग

भारतीय संस्कृति का केंद्र हिंदू धर्म है, जो सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि एक व्यापक जीवन शैली है। भारतीय संस्कृति का लोकाचार हिंदू धर्म के सिद्धांतों और इसके सह-अस्तित्व और वसुधैव कुटुंबकम के मूल दर्शन के साथ जुड़ा हुआ है।

ललित गर्ग

राहुल गांधी ने अहमदाबाद में विश्व कप क्रिकेट के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार के बाद राजस्थान में चुनावी भाषण में मोदी के खिलाफ 'पनौती' जैसे आपत्तिजनक, विवादित एवं अपशब्द का इस्तेमाल किया था।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ की गयी 'पनौती' (अपशकुन), जेबकतरा एवं कर्जमाफी जैसी अशोभनीय टिप्पणियों के कारण निशाने पर हैं। चुनाव आयोग (ईसी) ने हालिया टिप्पणियों के लिए राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी करके निर्णायक कार्रवाई की है। यह कार्रवाई सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा चुनाव आयोग में दर्ज की गई एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए की गयी है। चुनाव आयोग ने जहां पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा पर चिंता व्यक्त की वही भाजपा ने तर्क दिया कि ऐसी भाषा एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता के लिए 'अशोभनीय' है। पिछले लम्बे दौर से विश्वनेता के रूप में प्रतिष्ठित देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दर्शन, उनके व्यक्तित्व, उनकी बढ़ती ख्याति, उनकी बहुआयामी योजनाओं व उनकी कार्य-पद्धतियों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में विपक्षी नेताओं और विशेषतः कांग्रेस नेताओं ने अमर्यादित, अशिष्ट, छिछालेदार भाषा का उपयोग कर राजनीतिक मर्यादाओं को तार-तार कर दिया है। विडम्बना देखिये कि मोदी को गालियां देकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करने वाले राहुल गांधी इसका खामियाजा भी भुगतते रहे हैं, लेकिन राजनीतिक अपरिवक्वता के कारण वे कोई सबक लेने का तैयार नहीं है।

निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी को याद दिलाया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता नेताओं को राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ असत्यापित आरोप लगाने से रोकती है। लेकिन राहुल गांधी ने राजस्थान में हाल की रैलियों में प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए उनके लिए 'पनौती', जेबकतरे और अन्य विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया था। राहुल गांधी के ये अशोभनीय एवं मर्यादाहीन बयान क्या रंग लायेगा, यह भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन स्वस्थ एवं आदर्श लोकतंत्र के लिये देश के प्रधानमंत्री के लिये इस तरह के निम्न, स्तरहीन एवं अमर्यादित शब्दों का प्रयोग होना, एक विडम्बना है, एक त्रासदी है, एक शर्मनाक स्थिति है। केवल कांग्रेस ही नहीं, अन्य राजनीतिक दल के नेता भी ऐसी अपरिपक्वता एवं अशालीनता का परिचय देते रहे हैं। पिछले नौ वर्षों में उद्योगपतियों को चौदह लाख करोड़ रुपये की छूट देने के आरोप भी सत्यता से परे, तथ्यहीन, भ्रामक एवं गुमराह करने वाले हैं। 'जेबकतरे' शब्द का प्रयोग करते हुए आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री लोगों का ध्यान भटकाते हैं। जबकि उद्योगपति गौतम अडानी उनकी (लोगों की) जेब से पैसे निकालते हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि जेबकतरे इसी तरह काम करते हैं। आयोग ने राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बारे में भी बताया जिसमें कहा गया था कि अगर संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है तो प्रतिष्ठा के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 में संरक्षित जीवन के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। इन दो अधिकारों को संतुलित करना एक संवैधानिक आवश्यकता है। लेकिन राहुल गांधी को यह संतुलन साधना कहा आता है?

राहुल गांधी ने अहमदाबाद में विश्व कप क्रिकेट के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार के बाद राजस्थान में चुनावी भाषण में मोदी के खिलाफ 'पनौती' जैसे आपत्तिजनक, विवादित एवं अपशब्द का इस्तेमाल किया था। यह एक शब्दभर नहीं है, बल्कि अनेक कुटिलताओं की अभिव्यक्ति है, 'पनौती' मोटे तौर पर ऐसे शख्स के लिये उपयोग किया जाता है, जिसकी मौजूदगी होने भर से बनता काम बिगड़ जाता है। आम तौर पर पनौती शब्द ऐसे व्यक्ति के लिए इंगित किया जाता है जो बुरी किस्मत लाता है। वैसे इसका किसी ज्ञान-विज्ञान और तर्क से नाता नहीं है। जाने-माने भाषाविद् डॉक्टर सुरेश पंत के मुताबिक, हिंदी में -औती प्रत्यय से अनेक शब्द बनते हैं। इनमें कटौती, चुनौती, मनौती, बपौती इत्यादि शामिल हैं। पनौती शब्द नकारात्मकता एवं अशुभता का सूचक है। पनौती को शनि की बुरी दशा का समय माना जाता है। इसका मतलब बाढ़ भी होता है। पनौती तमिल शब्द पन्नादाई का अपभ्रंश भी है। इसका मतलब होता है 'एक ढीला बुना हुआ कपड़ा' या 'मूर्ख'।

बात केवल राहुल गांधी की ही नहीं है, कौन भूल सकता है सोनिया गांधी का वह बयान, जिसने वास्तव में गुजरात की जनता को झकझोर कर रख दिया था। तब सोनिया ने गुजरात के तत्कालीन और बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 'मौत का सौदागर' बताया था। सोनिया ने कहा था, "मेरा पूरा भरोसा है कि आप ऐसे लोगों को मंजूर नहीं करेंगे जो जहर के बीज बोते हैं।" 'मौत का सौदागर' के बाद 'जहर की खेती' के इस बयान ने गुजरात ही नहीं, देश की जनता की भावना को जगा दिया। नतीजा लोकसभा चुनाव के परिणाम के रूप में सामने आया, जिसमें बीजेपी को 278 और कांग्रेस को 45 सीटें मिलीं। जनता को बेवकूफ एवं नासमझ समझने की भूल कांग्रेस बार-बार करती रही है और बार-बार मात खाती रही है। इन चुनावों में भी ऐसी मात खाने को मिले तो कोई आश्चर्य नहीं है। क्योंकि जनता अपने सर्वोच्च नेतृत्व को मर्यादाहीन तो कत्तई नहीं देखना चाहती। कभी पूर्व कैबिनेट मंत्री मणिशंकर अय्यर मोदी को 'नीच' तक कह देते हैं तो राहुल तो सर्जिकल स्ट्राइक पर 'खून की दलाली' जैसे आरोप लगाते रहे हैं।

नोटबंदी को लेकर जहां पूरा देश नरेन्द्र मोदी के साथ खड़ा था, तब विपक्ष को काले कारोबारियों के साथ खड़ा होने में जरा भी शर्म नहीं आई। विपक्ष ने दुनिया के कुख्यात रहे तानाशाह हिटलर, मुसोलिनी, कर्नल गद्दाफी से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना कर डाली। इस तरह के स्तरहीन, ओछे एवं अमर्यादित बयानों से न केवल विपक्ष दलों के नेताओं बल्कि कांग्रेस पार्टी की न केवल फजीहत होती रही है, बल्कि उसकी बौखलाहट को दर्शाती रही है। इस तरह के लोग राजनीति में जगह बनाने के लिये ऐसी अनुशासनहीनता एवं अशिष्टता करते हैं। राहुल के इस तरह के ओछे, स्तरहीन एवं अशालीन शब्दों के प्रयोग का एक लम्बा सिलसिला है। मोदी पर गाली की बौछार में कभी उनको सांप, बिच्छू और गंदा आदमी कहा गया था। तो कभी लहू पुरुष, पानी पुरुष और असत्य का सौदागर भी बताया। सत्ता के शीर्ष पर बैठकर यदि इस तरह जनतंत्र के आदर्शों को भुला दिया जाता है तो वहां लोकतंत्र के आदर्शों की रक्षा नहीं हो सकती। राजनैतिक लोगों से महात्मा बनने की आशा नहीं की जा सकती, पर वे अशालीनता एवं अमर्यादा पर उतर आये, यह ठीक नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरा ईश्वर दरिद्र-नारायणों में रहता है।' आज यदि उनके भक्तों-कांग्रेसजनों से यही प्रश्न पूछा जाये तो संभवतः यही उत्तर मिलेगा कि हमारा ईश्वर कुर्सी में रहता है, सत्ता में रहता है। तभी उनमें अच्छाई-बुराई न दिखाई देकर केवल सत्तालोलुपता दिखती है।

ये तथाकथित नेता गाली ही नहीं देते रहे, बल्कि गोली तक की भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन कोई गाली या गोली मोदी का बाल भी बांका नहीं कर सकेंगी क्योंकि वे जनसमर्थन से इन ऊंचाइयों को पाया है। मोदी को तो बोटी-बोटी काट देने की धमकी खुलेआम दी गयी। किसी ने मोदी को रैबिज से पीड़ति बताया तो किसी ने उन्हें केवल चूहे मात्र माना। चायवाले से तो वे चर्चित हैं। लेकिन मोदी के व्यक्तित्व की ऊंचाई एवं गहराई है कि उन्होंने अपने विरोध को सदैव विनोद माना। मोदी को बार-बार कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है। चुनाव का समय हो या सामान्य कार्य के दिवस मोदी ने कम गालियां नहीं खाईं। उनके विचारों को, कार्यक्रमों को, देश के लिये कुछ नया करने के संकल्प को बार-बार मारा जा रहा है। लेकिन मोदी भारत की आजादी के बाद बनी सरकारों के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें कोई गोली या गाली नहीं मार सकती। क्योंकि मोदी की राजनीति व धर्म का आधार सत्ता नहीं, सेवा है, राष्ट्र-निर्माण है। जनता को भयमुक्त व वास्तविक आजादी दिलाना उनका लक्ष्य है। वे सम्पूर्ण भारतीयता की अमर धरोहर हैं।

संपादक की कलम से

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के द्वार

हिमाचल कर्मचारियों के हितों का मक्का है और इसीलिए प्रदेश के संसाधन इस वर्ग को पूजनीय-वंदनीय बना देते हैं। कमोबेश हर सरकार को अपने संसाधनों से इसी प्रक्रिया में खुद को अव्वल साबित करने के लिए सामग्री जुटानी पड़ती है। राज्य ने कर्मचारी मुद्दों को इतनी तरजीह दे डाली है कि अब राजनीति के डाली-डाली इनके प्रति झुकी रहती है। ओल्ड पेंशन की गोल्ड माइन खोल कर सत्ता में आई कांग्रेस अब प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के रास्ते कर्मचारी वर्ग के अधिकारों को न्योता दे रही है। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल एक तरह की सियासी रस्साकशी बनता रहा है। कर्मचारी वर्ग को कानूनी हक दिलाने के लिए बार-बार इसके दरवाजे खोले जाते हैं या फिर सारे दांव या कानूनी पेंच अदालत के मार्फत संबोधित किए जाते हैं। पूर्ववर्ती जयराम सरकार ने कर्मचारी कवच को प्रशासनिक ट्रिब्यूनल से उखाडक़र माननीय अदालत के दायरे तक पहुंचा दिया था। उस समय इक्कीस हजार कर्मचारी मामलों का दहेज अदालत के दरवाजे पहुंच गया था और अब फिर कवायद यह कि इस विषय को स्वतंत्र ट्रिब्यूनल के अधीन लाया जाए। दोनों ही तरह के फैसलों के तर्क कर्मचारी वर्ग के लिहाज से महत्त्वपूर्ण रहे हैं, फिर भी हर परिस्थिति के संकट, निर्णयों की गति तथा नए मामलों की प्रगति आड़े आती है। कर्मचारी मामलों के संदर्भ प्रायः ट्रांसफर पालिसी न होने के कारणों से टकराते हैं। वेतन विसंगतियों, स्तरोन्नत होने के मसले तथा कॉडर से संबंधित मामले जब इक्ट्ठे होते हैं, तो इन्हें निपटाने का दबाव एडियां रगड़ता है। जाहिर है प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना का उद्देश्य तथा ऐसी पद्धति के कार्यान्वयन से सहजता व सरलता का तकाजा दिखाई देता है, लेकिन व्यावहारिकता के प्रश्रपर कानून के दस्तखत बदल जाते हैं।

वही कानून अदालत की परिपाटी में अपनी परंपरा और निष्पक्षता की दृढ़ता से विश्वास तो पैदा करता है, लेकिन कर्मचारी मामलों के निपटारे समयावधि तय नहीं करते। इसके विपरीत प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की सार्थकता में कानून की गतिशीलता व विकेंद्रीयकरण स्पष्ट है। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल अपनी परिपाटी में मंडी व धर्मशाला की सर्किट बैंच के जरिए न केवल कर्मचारी वर्ग के नजदीक पहुंचती है, बल्कि न्याय पाने की क्षमता को सहज व सस्ता बनाती है। हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में कानूनी ढांचे की यह विसंगति हर पहलू में रही है और इसीलिए हाई कोर्ट की सर्किट या स्थायी खंडपीठ की मांग पिछले चालीस सालों से धर्मशाला के लिए हो रही है। ऐसे में कर्मचारी मामलों की मात्रात्मक अर्जियों को शिमला में हाई कोर्ट का समय व प्राथमिकता नहीं मिल पाती। यह दीगर है कि फैसलों की गुणवत्ता पर प्रश्न उठाते हुए भाजपा की अलग-अलग सरकारों ने कर्मचारियों को हाई कोर्ट का बार-बार विकल्प दिया, लेकिन इक्कीस हजार मामले अगर स्थानांतरित हो जाएं, तो अदालत के लिए इनमें अपनी प्राथमिक भूमिका निभाना कठिन हो जाएगा। ऐसे में फिर एक नए प्रयोग के तहत सुक्खू सरकार ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के दरवाजे खोलने की इच्छा प्रकट की है। अभी इससे संबंधित प्रक्रिया ने दस्तक दी है और इसे मुकम्मल होने की स्थिति तक कुछ समय का इंतजार रहेगा। दोनों विकल्पों के बावजूद न हाई कोर्ट में मामले घटे और न ही प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के रास्ते कर्मचारी मसले कम हुए।

कानून की शरण में कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक मानी गए प्रशासनिक ट्रिब्यूनल व्यवस्था के बावजूद निष्कर्ष यही है कि कॉडर-कॉडर, पद-पद और दफ्तर-दफ्तर, कार्य संस्कृति सुधारने से कहीं अधिक दबाव यह है कि हजारों कर्मचारी कानूनी दांव-पेंच तक ही सिमट रहे हैं। पिछले काफी वर्षों से प्रदेश सरकारों ने कर्मचारी मसलों को तरजीह देते हुए उचित-अनुचित के बजाय उनके स्वार्थों को ही पोषित किया। न कभी प्रशासनिक सुधारों पर कोई महत्त्वपूर्ण फैसला हुआ और न ही सरकारी कार्यसंस्कृति में सुधार लाने के गंभीर प्रयास हुए। आश्चर्य यह कि हर साल सैकड़ों ट्रांसफर मामलों की आपत्तियां कानून की शरण पहुंच रही हैं, लेकिन न कोई ठोस स्थानांतरण नियम या नीति बनाने की जहमत उठाई गई और न ही कार्यसंस्कृति को अहमियत मिली। ऐसे में क्या उस आम नागरिक या मतदाता की सरकार से अपेक्षाएं पूरी हो रही हैं।

राय

अंतरिक्ष में नासा के दबदबे को खत्म करने का संकल्प पूरा करने के करीब पहुँच चुका है चाइना

हम आपको यह भी बता दें कि चीन के सरकारी मीडिया ने पिछले साल कहा था कि तियांगोंग पूरी तरह से चालू हो गया है। चीन ने यह भी कहा था कि ऐसे में जबकि आईएसएस अपना जीवनकाल समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है तब चीन अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों में कोई ढील नहीं देगा।

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के नेतृत्व वाला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अपने जीवनकाल के अंत के करीब पहुँच चुका है। ऐसे में अब चीन की नजर अंतरिक्ष का बादशाह बनने पर लग गयी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को निर्देश दे रखे हैं कि हर हाल में आने वाले समय में चीन को अंतरिक्ष की दुनिया का सरताज बनाना है। इसलिए चीनी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने अपने प्रयास तेज कर दिये हैं। अजरबैजान के बाकू में आयोजित 74वीं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस में चीन की अंतरिक्ष एजेंसी चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी (CAST) ने जो कुछ बताया है वह पूरी दुनिया को सावधान करने के लिए काफी है। हम आपको बता दें कि चीन की ओर से कहा गया है कि वह आने वाले वर्षों में अपने अंतरिक्ष स्टेशन को तीन से छह मॉड्यूल तक विस्तारित करने की योजना बना रहा है, जिससे अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के निकट वाले मिशनों के लिए एक वैकल्पिक मंच उपलब्ध हो सकेगा। चीन ने कहा है कि चूंकि नासा के नेतृत्व वाला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) का कार्यकाल समाप्त होने वाला है इसलिए दुनिया को अंतरिक्ष में अपने मिशनों के लिए एक विकल्प की जरूरत है जोकि वह उपलब्ध करायेगा। जरा सोचिये! चीन जब धरती पर रह कर ही दुनिया की इतनी जासूसी करता है तो ऐसे में यदि अंतरिक्ष में उसकी बादशाहत हो गयी तो वह अपना पूरा अमला ही दुनिया की निगरानी करने में लगा देगा।

जहां तक अंतरिक्ष में चीनी स्टेशन की बात है तो उसके बारे में बताया गया है कि चीनी अंतरिक्ष स्टेशन का परिचालन जीवनकाल 15 वर्ष से अधिक होगा। पहले इसका जीवनकाल मात्र 10 वर्षों का ही बताया गया था। हम आपको बता दें कि चीन का स्व-निर्मित अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे तियांगोंग या चीनी में सेलेस्टियल पैलेस के रूप में भी जाना जाता है, वह 2022 के अंत से पूरी तरह चालू हो गया है। चीन का अंतरिक्ष स्टेशन 450 किमी (280 मील) की कक्षीय ऊंचाई पर है और अभी यहां अधिकतम तीन अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं। अभी चीन का जो अंतरिक्ष स्टेशन है वह आईएसएस के मुकाबले 40 प्रतिशत ही है क्योंकि नासा के नेतृत्व वाला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक साथ सात अंतरिक्ष यात्रियों को संभाल सकता है जबकि चीन का स्टेशन मात्र तीन अंतरिक्ष यात्रियों को ही एक साथ रख सकता है। इसीलिए चीन ने अब अपने अंतरिक्ष स्टेशन के छह मॉड्यूल तक विस्तार की योजना बनाई है। हम आपको बता दें कि दो दशकों से ज्यादा समय से अंतरिक्ष में मौजूद आईएसएस के 2030 के बाद निष्क्रिय होने की उम्मीद है। उससे पहले चीन का प्रयास है कि वह एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बन जाये। हम आपको यह भी बता दें कि चीन के सरकारी मीडिया ने पिछले साल कहा था कि तियांगोंग पूरी तरह से चालू हो गया है। चीन ने यह भी कहा था कि ऐसे में जबकि आईएसएस अपना जीवनकाल समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है तब चीन अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों में कोई ढील नहीं देगा। चीन का यह भी दावा है कि कई देशों ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चीनी स्टेशन पर भेजने के लिए आग्रह करना शुरू भी कर दिया है।

दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित मेरी दिल्ली

विकास खितौलिया खटीक
(लेखक, शोधकर्ता एवं समाजसेवी)

कुछ पाने की हमने बड़ी कीमत चुकाई, अपनी साँसों को खुद हमने जहरीली हवा पिलाई।

वायु, जल और भोजन इनके बिना मनुष्य जीवन संभव नहीं हैं। इन तीनों में वायु सबसे अनिवार्य है क्योंकि इसके बिना मानव का दो मिनट भी जीवित रहना मुश्किल है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि स्वच्छ वायु हमारे लिए कितना जरूरी है। वर्ष 2014-15 से देश की राजधानी दिल्ली में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण का अपने चरम पर पहुँचना बहुत आम हो गया है। विशेष तौर पर नवंबर माह से वायु प्रदूषण का स्तर इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है कि लोगों को सांस लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बीच में एकाध दिन तेज हवा चलने या वर्षा होने से प्रदूषण में कुछ हद तक कमी आने की घटना को छोड़ दें तो इसका स्तर अधिकांशतया गंभीर स्थिति में ही है। हालात की गंभीरता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली में तत्काल प्रभाव से ग्रेप का चौथा चरण लागू कर दिया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा 14 मिलियन या उससे अधिक की आबादी वाले मेगासिटीज के लिए संकलित वायु गुणवत्ता डेटा के अनुसार, भारतीय राजधानी एक बार फिर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पाया गया है और मुंबई चौथे स्थान पर है। मिस्र में ग्रेटर काहिरा दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है, इसके बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बीजिंग पांचवें स्थान पर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है। समाचारपत्र बताते हैं कि खराब हवा में सांस लेने की वजह से दिल्ली में रहने वालों की आयु 11.9 वर्ष कम हो सकती है। वायु प्रदूषण एक राष्ट्रीय आपदा बनता जा रहा है। दिल्ली सहित पड़ोसी राज्यों और देश के विभिन्न प्रदेशों के शहरी क्षेत्रों में AQI का स्तर लगातार बढ़ रहा है।

मानव द्वारा पृथ्वी पर फैलाए गए प्रदूषण के कारण मानव को ही नित नए-नए रोगों से सामना करना पड़ता है। वायु प्रदूषण से सांस लेने में कठिनाई, घबराहट, अस्थमा, सिर दर्द, खांसी, जुखाम, बुखार, चिड़चिड़ापन, त्वचा रोग और श्वसन व हृदय संबंधी अन्य बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। बच्चे, बुर्जुग, युवा, महिलाएं सभी परेशान हैं। घर के अंदर और बाहर वायु प्रदूषण की स्थिति के कारण होने वाली कुल मौतों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि विकासशील देशों में रहने वाले पांच साल से कम उम्र के बच्चों पर वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। फिर भी शासन प्रशासन बेबस एवं मौन बैठा है। बैठकें होती हैं फिर स्कूल बंद किए जाते हैं, भारी वाहनों पर बंदिशें, निर्माण कार्य बंद, दिवाली शॉपिंग से पहले मास्क खरीदे जाते है, आड- इवेन का सुझाव, पर्यटकों ने तो दिल्ली से मुँह मोड़ लिया, काम करने के घंटे घट रहे हैं, आर्थिक नुकसान हो रहा है, लोग एयर प्यूरिफायर एवं नेबुलाइजर अपने-अपने घरों में ऑन करके बैठते हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति घुट घुटकर जीने को मजबूर है।

स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 के अनुसार अकेले भारत में 12.4 लाख लोग हर वर्ष इसका शिकार बन जाते हैं। अब तक प्रदूषण की जद में केवल जन्मे ही आते थे, मगर जर्नल नेचर कम्युनिकेशंस में छपे नए शोध ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है, जिसके मुताबिक बढ़ते प्रदूषण का असर अब अजन्मों पर भी दिखने लगा है। यह पहला मौका है जब किसी शोध में यह पाया गया कि मां की सांस के माध्यम से अंदर गए ब्लैक कार्बन के कण उनके अजन्मे बच्चों (भ्रूण) के अंदर तक पहुंच सकते हैं। अध्ययन में भ्रूण के किनारों और गर्भनाल में वायु प्रदूषण के हजारों कण पाए गए, जो दर्शाता है कि अजन्में बच्चे भी मोटर गाड़ियों, कारखानों और ईंधन के जलने से उत्पन्न हुए ब्लैक कार्बन के संपर्क में आ रहे हैं। गौरतलब है कि गर्भनाल किसी महिला के शरीर का एक अभिन्न अंग होती है, जो गर्भावस्था के दौरान बच्चे को पोषण और सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है और मां के खून के साथ आने वाली हानिकारक चीजों को भ्रूण तक पहुंचने से रोकती। बच्चा इसी के सहारे मां के गर्भ में जीवित रहता है। यदि वायु प्रदूषण के कण इस अभेद सुरक्षा दीवार को भी भेद सकते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले वक्त में इसका व्यापक और हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, दिल्ली जो लगभग 19 मिलियन लोगों का शहर है, एक गैस चैम्बर में बदल चुका है। यहाँ की हवा रहने लायक नहीं रही है। इधर केंद्र सरकार, राज्य एवं सम्बंधित निकाय सभी एक-दूसरे पर आरोप- प्रत्यारोप लगा रहे हैं। प्रतिदिन सुबह उठकर दिल्ली वालो का स्वागत करने के लिए, एक बहुत बड़ी धुंध की चादर हाजिर है

विगत कुछ वर्षों से दिल्ली लगातार प्रदूषण की गिरफ्त में है। सर्दियों में पंजाब और हरियाणा से आने वाले पराली के धुएं के कारण, गर्मियों में हरियाणा और राजस्थान से आने वाली धूल के कारण और बरसात के मौसम में जल भराव के कारण ट्रैफिक जाम से उत्पन्न धुआं वायु प्रदूषण का प्रमुख स्त्रोत है। वैवाहिक अवसर, पर्व-उत्सव आदि पर भी आतिशबाजी निरंतर बढ़ती जा रही है। दिल्ली में बंदिशें लगा दी जाती हैं, फिर भी अनुचित तरीके से खूब पटाखे और प्रदूषण की गतिविधियां जारी रहती हैं। इसके अतिरिक्त अनधिकृत रूप से चल रही फैक्ट्रियों और ढाबों का धुआं भी जीवन के लिए संकट बन रहे हैं।

बढ़ती आबादी के परिवहन के लिए वाहनों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। निजी वाहनों के स्टेटस सिंबल के शौक ने वाहनों की संख्या में भी बेतहाशा वृद्धि की है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था आबादी के अनुपात में बेहद कमजोर है। यह कारण ही दिल्ली की हवा को जहरीली बनाने के लिए पर्याप्त है। एक सर्वे के अनुसार दिल्ली में 23 लाख 80 हजार वाहनों के पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं है। प्रश्न यह भी है कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना ये वाहन किस नियम के तहत चल रहे हैं और इन पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई? फिर भी मार्च 2023 में दिल्ली सरकार द्वारा पेश की गई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर वाहनों की कुल संख्या में 35 प्रतिशत की वार्षिक गिरावट देखी गई, क्योंकि शहर सरकार ने अधिक उम्र के वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। दिल्ली सरकार द्वारा 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के बाद से 35.38 प्रतिशत की कमी दर्शाती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर मेट्रो रेलवे प्रणाली नहीं होती तो दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण और भी बदतर होता। दिल्ली सरकार को परिवहन क्षेत्र में दिल्ली की जनता को बिजली संयंत्रों और सीएनजी के उपयोग को प्रोत्साहित करें।

वायु प्रदूषण का एक और प्रमुख कारण है पड़ोसी राज्यों में पराली जलना। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दिल्ली पड़ोसी राज्य कोई भी तरीका अपनाएं लेकिन पराली जलने की घटनाएं तुरंत रुकनी चाहिए। फिर भी न्यायालय के इस आदेश के बाद भी पराली जलाने के मामले जारी हैं। अकेले पंजाब में 11 नवंबर को 104 मामले, 12 नवंबर को 987 मामले और 13 नवंबर को 1624 मामले सामने आए हैं। पिछले कुछ वर्षो में पराली जलाने के मामले वर्ष 2021 में 32734, वर्ष 2022 में 29999 जबकि वर्ष 2023 में लगभग 18500 हैं। अब तक लगभग 3500 संख्या के साथ सबसे ज्यादा मामले प्रदेश के संगरूर नामक क्षेत्र से दर्ज हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्थाएं इन किसानों को समझाने में और जनभागीदारी बढ़ाने में पूरी तरह असफल रही हैं। क्या यह सामान्य व्यक्ति के जीवन से खिलवाड़ और न्यायालय के आदेश की अवमानना नहीं है? एक विडंबना यह भी है कि दिल्ली में जितनी पराली जलाई जाती है, उससे कई गुना अधिक यहां रिहायशी और औद्योगिक क्षेत्रों में प्लास्टिक जलाया जाता है। पराली जलाने की बात बेहिसाब प्लास्टिक के कूड़े जलाने के दुष्कृत्य को छिपाने के लिए भी की जाती है। इसका ठोस उपाय यह है कि राजधानी दिल्ली में प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। प्लास्टिक को जलाने के बजाय रासायनिक तरीके से निस्तारित किया जाना चाहिए।

तेजी से बढ़ती जनसंख्या एवं माइग्रेशन भी एक प्रमुख कारण हैं। दिल्ली हमेशा से ही आर्कषण का केन्द्र रही है, जनसंख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए अधिक संसाधनों की जरूरत पड़ती है जिनके कारण भी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। यह अनेक कार्य कलापों का शहर है; जहां बड़े पैमाने वाले उद्योग, व्यापारिक तथा सेवा उन्मुख गतिविधियां होती रहती हैं। दिल्ली, भारत का सबसे अधिक रफ्तार से बढ़ने वाला शहर है, जहां रोज 1000 लोगों की आबादी इसमें जुड़ते जाती है। जिनमें विशेषकर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश व बिहार से आए गरीब लोग शामिल हैं। इस बढ़ती आबादी के उत्सर्जित अपशिष्ट से दिल्ली के चारों ओर कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं। इसके निस्तारण के लिए वैसे तो अब तक कई प्रकार के उपाय खोजे गए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उपाय व्यावहारिक रूप से क्रियान्वित नहीं हो सका है। हमें इस बारे में नए सिरे से विचार करना चाहिए। उसके निस्तारण के लिए जलाने की प्रक्रिया का वायु प्रदूषण में विशेष योगदान है। दिल्ली और राजस्थान के बीच घने जंगल तो कभी नहीं रहे, पर उष्णकटिबंधीय वृक्ष बबूल, मंदार जैसे सघन वृक्ष तो थे ही, जिनका विनाश कर खेती योग्य जमीन बनाने से लेकर औद्योगीकरण और कालोनियां बनाने के लिए किया जाता रहा है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि आज रेगिस्तानी शीत और लू ने दिल्ली तक पहुंचकर उसे दमघोटू शहर में तब्दील कर दिया है।

भारतीय ज्ञान परंपरा में वायु प्रदूषण के समाधान विद्यमान हैं, क्या आज उसका अनुसरण आवश्यक नहीं है? विगत कुछ वर्षो से पानी के छिड़काव को इसके उपचार के रूप में देखा जाता है। एक ओर यमुना सूख रही है, पीने के पानी की किल्लत है और दूसरी ओर कृत्रिम बरसात के रूप में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। यह विकल्प विनाशकारी है। सूखते जल स्रोत के युग में इतना पानी कहां से आएगा, यह भी यक्ष प्रश्न है। इस विकट समस्या का स्थायी हल तभी संभव है जब दिल्ली में हरित क्रांति को प्रोत्साहित किया जाए। कम जगह में उगने वाले ताड़, खजूर, सुपाड़ी जैसे ऊंचे वृक्षों के पौधे लगाए जाएं। दिल्ली के चारों ओर वनीकरण को बढ़ावा दिया जाए, विशेषकर राजस्थान के रेगिस्तान और दिल्ली के बीच जंगलों को पुनर्स्थापित किया जाय। आज अमेरिका की हवा दुनिया में सबसे साफ है, वायु प्रदूषण से निजात पाने के लिए हमें इस प्रकार के देशों से भी योजना बनाने में मदद लेनी चाहिए। नब्बे के दशक में बीजिंग और दिल्ली एक ही पन्ने पर थे, जिसमें दोनों शहरों को प्रदूषण से चुनौती दी गई। आज दिल्ली का प्रदूषण खतरनाक स्तर को छू रहा है लेकिन बीजिंग काफी वायु प्रबंधन के जरिए प्रदूषण में कटौती करने में कामयाब रहा है। वायु प्रदूषण को राष्ट्रीय आपदा मानते हुए क्षेत्रीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंतन के साथ-साथ दोषियों पर त्वरित और कठोर दंड का विधान होना नितांत आवश्यक है। वायु प्रदूषण प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है जिस पर ध्यान देने के साथ ही सभी के सामूहिक प्रयासों से सुलझाने की आवश्यकता है।

SME प्लेटफॉर्म से BSE के मेन बोर्ड में शामिल होने के लिए बीएसई ने जारी की नई गाइडलाइन, 7 प्वाइंट में समझिए नए नियम

बीएसई ने उन एसएमई के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं जो बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म को छोड़कर बीएसई मुख्य बोर्ड में शामिल होना चाहते हैं। मेन बोर्ड का मतलब बीएसई की एसएमई प्लेटफॉर्म को छोड़कर 100 या 300 कंपनियों की सूची में शामिल होना है। जानिए नियमों में क्या किए गए बदलाव और कब से लागू होगी नई गाइडलाइन। पढ़िए पूरी खबर।

नई दिल्ली। वैसे स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज जो बीएसई की SME प्लेटफॉर्म से निकलकर बीएसई की मेनबोर्ड में शामिल होना चाहते हैं उन उद्यमों के लिए बीएसई ने कुछ गाइडलाइन जारी किया है। मेन बोर्ड का मतलब बीएसई की टॉप 100 या टॉप 300 कंपनियों की लिस्ट में शामिल होना है।

कब से लागू होगी ये गाइडलाइन?

बीएसई ने कहा कि ये नई गाइडलाइन 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएगी। आपको बता दें कि बीएसई ने नई गाइडलाइन के अलावा SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग के लिए पात्रता मानदंड में भी बदलाव किया है।

क्या है नई गाइडलाइन?

बीएसई की गाइडलाइन के तहत आवेदक के पास पिछले दो वित्तीय वर्षों में कम से कम 15 करोड़ रुपये का नेट वर्थ होना चाहिए।

आवेदनकर्ता एसएमई उद्यमों के पास कम से कम तीन साल के लिए एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होना जरूरी है।

बीएसई की मेनबोर्ड में ट्रांसफर होने से पहले आवेदनकर्ता के पास 250 पब्लिक शेयरहोल्डर होने चाहिए।

एसएमई आवेदनकर्ता को कम से कम तीन वित्तीय वर्षों में से किसी दो के लिए सकारात्मक परिचालन लाभ होना चाहिए और एक्सचेंज में माइग्रेशन आवेदन करने के तत्काल वित्तीय वर्ष में प्रॉफिट आफटर टैक्स (PAT) पॉजिटिव होना चाहिए।

आवेदक की चुकता इक्विटी पूंजी 10 करोड़ रुपये से अधिक होनी चाहिए और एमकैप कम से कम 25 करोड़ रुपये होना चाहिए। आवेदक कंपनी को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) द्वारा स्वीकार की गई कोई भी समापन याचिका प्राप्त नहीं होनी चाहिए और पिछले तीन साल में फर्म के खिलाफ किसी भी स्टॉक एक्सचेंज द्वारा एसएमई और उसके प्रमोटरों के खिलाफ व्यापार को निलंबित करने जैसी कोई महत्वपूर्ण नियामक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

आवेदक कंपनी, उसके प्रमोटरों के साथ-साथ उसकी सहायक कंपनी को बाजार नियामक सेबी द्वारा प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए।

अब तक कितनी कंपनियां मेनबोर्ड में हुई ट्रांसफर?

आंकड़ों के मुताबिक अब तक, 464 कंपनियां बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुई है जिनमें से 181 कंपनियां मेनबोर्ड में ट्रांसफर हुई है।

एफपीआई ने रोकी बिकवाली, नवंबर में अब तक 378.2 करोड़ रुपये का किया निवेश

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने शेयर बाजार में अपनी लगातार बिकवाली रोक दी और इस महीने अब तक 378 .2 करोड़ रुपये का निवेश किया हालांकि एफपीआई ने अक्टूबर में 24548 करोड़ रुपये और सितंबर में 14767 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे। जानिए एफपीआई ने क्यों रोकी बिकवाली और अब तक इस कैलेंडर ईयर में कितना किया निवेश।

दिल्ली। नवंबर महीने में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने शेयर बाजार से जारी अपने बिकवाली को रोक दिया और 378 करोड़ रुपये का निवेश किया। यह निवेश अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेज गिरावट के कारण आया है।

पिछले महीने एफपीआई ने इतने करोड़ के बेचे थे शेयर

डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक एफपीआई ने अक्टूबर में 24,548 करोड़ रुपये और सितंबर में 14,767 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे।

हालांकि निकासी से पहले, एफपीआई मार्च से अगस्त तक इन छह महीनों में लगातार निवेश किया था और इस अवधि के दौरान 1.74 लाख करोड़ रुपये बाजार में डाले थे। इस कैलेंडर वर्ष में अब तक एफपीआई ने 96,340 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

यस सिक्योरिटीज इंडिया में इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज रिसर्च के रणनीतिकार हितेश जैन ने कहा,

हमारा मानना है कि इमरजिंग मार्केट में जोखिम उठाने की क्षमता में सुधार और अमेरिका में जोखिम-मुक्त यील्ड में गिरावट एफपीआई प्रवाह को भारत की ओर आकर्षित करेगी।

इस महीने एफपीआई ने अब तक कितना किया निवेश?

आंकड़ों के मुताबिक, एफपीआई ने इस महीने (24 नवंबर तक) भारतीय शेयरों में 378.2 करोड़ रुपये का निवेश किया है। विदेशी निवेशक इस महीने चार दिन खरीदार रहे और शुक्रवार को 2,625 करोड़ रुपये की बड़ी खरीदारी की।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा,

अक्टूबर के मध्य में अमेरिका में मुद्रास्फीति में उम्मीद से बेहतर गिरावट ने बाजार को यह मानने का विश्वास दिला दिया है कि फेड ने दरों में बढ़ोतरी कर दी है। नतीजतन, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी से गिरावट आई है और 10-वर्षीय बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड अक्टूबर के मध्य में 5 प्रतिशत से घटकर अब 4.40 प्रतिशत हो गई है। इससे एफपीआई को अपनी बिकवाली धीमी करने पर मजबूर होना पड़ा है

मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इंडिया के एसोसिएट डायरेक्टर - मैनेजर रिसर्च, हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा,

अनिश्चित वैश्विक कारक भारत के इक्विटी बाजारों में विदेशी निवेश की दिशा तय कर रहे हैं

डेट मार्केट में आए इतने करोड़

आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में 6,381 करोड़ रुपये प्राप्त करने के बाद समीक्षाधीन अवधि में डेट मार्केट ने 12,400 करोड़ रुपये आकर्षित किए।

इनसाइड

हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय पुरानी बीमारी छिपाना पड़ सकता है भारी

स्वास्थ्य बीमा खरीदते समय मधुमेह और रक्तचाप (बीपी) जैसी अन्य पुरानी स्थितियों को छिपाना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। इस आधार पर बीमा कंपनियां क्षति के लिए मुआवजा देने से इनकार कर सकती हैं और यहां तक कि बीमा अनुबंध भी समाप्त कर सकती हैं। हाल में हुए पॉलिसीबाजार सर्वेक्षण के अनुसार 25 प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा आवेदन पुरानी बीमारियों को छिपाने के आधार पर खारिज कर दिए जाते हैं।

नई दिल्ली। हेल्थ इंश्योरेंस उत्पाद की खरीदारी के दौरान शुगर व ब्लड प्रेशर (बीपी) जैसी अन्य पुरानी बीमारियों को छिपाना भारी पड़ सकता है। इस आधार पर इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम को खारिज कर सकती है और प्रीमियम का पैसा जब्त कर इंश्योरेंस पॉलिसी भी रद कर सकती है। पॉलिसी बाजार के हालिया सर्वे के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस के जितने क्लेम खारिज होते हैं, उनमें 25 प्रतिशत का आधार पुरानी बीमारियों को छिपाना होता है। वहीं 50 प्रतिशत क्लेम इंश्योरेंस उत्पाद की सीमित समझ की वजह से खारिज होते हैं। कंपनी ने यह खुलासा इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच दो लाख क्लेम में से 30 हजार अस्वीकृत क्लेम के विश्लेषण के बाद किया है। जानकारों के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस के उत्पादों को लेकर उपभोक्ताओं की समझ सीमित होती है और कई बार वह ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। उदाहरण के लिए कई ऐसी बीमारी होती है जिनके क्लेम में वेटिंग पीरियड होता है। यह वेटिंग पीरियड एक माह, दो साल और चार साल तक का हो सकता है जो बीमारी पर निर्भर करता है। मान लीजिए अगर स्टोन की बीमारी का वेटिंग पीरियड दो साल का है तो इंश्योरेंस लेने के दो साल के बाद ही स्टोन के इलाज का क्लेम कंपनी देगी। पॉलिसी बाजार के सर्वे में पाया गया कि 18 प्रतिशत से अधिक क्लेम वेटिंग पीरियड पूरा न होने की वजह से खारिज कर दिए जाते हैं। मतलब क्लेम वेटिंग पीरियड पूरा होने के पहले फाइल किया गया था।

सर्वे में पाया गया कि 25 प्रतिशत क्लेम इसलिए खारिज हुए क्योंकि वे कवरेज से बाहर के थे। कई बार इंश्योरेंस उत्पाद में डे केयर या ओपीडी कवरेज शामिल नहीं होता है, लेकिन उपभोक्ता उसका क्लेम भी कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि इंश्योरेंस खरीदने वाले कवरेज के दायरे को ठीक से समझ ले। इलाज कराने से पहले पॉलिसी दस्तावेजों को सही से पढ़ने और समझने से इस प्रकार की अस्वीकृति को कम किया जा सकता है। 4.5 प्रतिशत क्लेम गलत तरीके से फाइल करने के कारण खारिज कर दिए जाते हैं। सर्वे में पाया गया कि 50 लाख से एक करोड़ वाले हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम खारिज करने का प्रतिशत पांच लाख तक के इंश्योरेंस की तुलना में काफी कम था। पॉलिसी बाजार के हेड हेल्थ इंश्योरेंस अमित छाबड़ा के मुताबिक अक्सर लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय पहले से मौजूद बीमारी को छिपा लेते हैं।

10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में 4 कंपनियों का संयुक्त MCap बढ़कर हुआ 65,671.35 करोड़, रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप गेनर

स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष 10 कंपनियों में से चार का संयुक्त बाजार मूल्य (एमकैप) पिछले सप्ताह बढ़कर 65671 .35 करोड़ रुपये हो गया। इन चारों कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज का एमकैप सबसे ज्यादा बढ़ा है। जानिए और कौन-कौन से कंपनियों के एमकैप में हुई बढ़ोतरी और किन कंपनियों के एमकैप में हुई गिरावट।

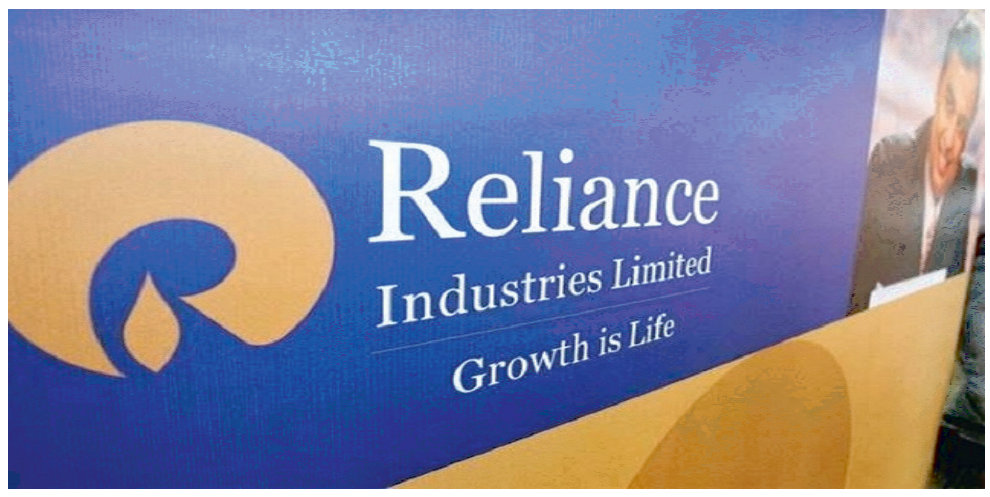

नई दिल्ली। शेयर बाजार की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से चार कंपनियों का संयुक्त मार्केट वैल्यूएशन (MCap) पिछले सप्ताह बढ़कर 65,671.35 करोड़ रुपये हो गया। इन चार कंपनियों में से सबसे अधिक एमकैप रिलायंस इंडस्ट्रीज का बढ़ा है।

इन कंपनियों का बढ़ा एमकैप

कुल 10 में से रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और भारती एयरटेल इन चार कंपनियों के एमकैप में बढ़ोतरी देखने को मिली है।

इनका घटा एमकैप

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, भारतीय स्टेट बैंक और बजाज फाइनेंस के एमकैप में गिरावट देखने को मिली है।

किस कंपनी का कितना बढ़ा एमकैप?

रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) का एमकैप सबसे अधिक 26,014.36 करोड़ रुपये बढ़कर 16,19,907.39 करोड़ रुपये रहा। एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) का एमकैप 20,490.9 करोड़ रुपये बढ़कर 11,62,706.71 करोड़ रुपये हो गया।

भारती एयरटेल (Bharti Airtel) का एमकैप 14,135.21 करोड़ रुपये बढ़कर 5,46,720.84 करोड़ रुपये हो गया और आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) का एमकैप 5,030.88 करोड़ रुपये बढ़कर 6,51,285.29 करोड़ रुपये हो गया।

इन कंपनियों का इतना घटा एमकैप

टीसीएस का एमकैप 16,484.03 करोड़ रुपये घटकर 12,65,153.60 करोड़ रुपये हो गया। बजाज फाइनेंस का एमकैप 12,202.87 करोड़ रुपये घटकर 4,33,966.53 करोड़ रुपये हो गया।

हिंदुस्तान यूनिलीवर का एमकैप 3,406.91 करोड़ रुपये गिरकर 5,90,910.45 करोड़ रुपये, भारतीय स्टेट बैंक का एमकैप 2,543.51 करोड़ रुपये घटकर 5,00,046.01 करोड़ रुपये रह गया।

आईटीसी का एमकैप 1,808.36 करोड़ रुपये घटकर 5,46,000.07 करोड़ रुपये रह गया और इंफोसिस का एमकैप 290.53 करोड़ रुपये घटकर 5,96,391.22 करोड़ रुपये रह गया।

रिलायंस सबसे मूल्यवान कंपनी

देश और बाजार की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में रिलायंस इंडस्ट्रीज का खिताब बरकरार है, दूसरे नंबर पर आईटी दिग्गज टीसीएस, तीसरे पर एचडीएफसी बैंक, चौथे पर आईसीआईसीआई बैंक, पांचवें पर इंफोसिस, छठे स्थान पर हिंदुस्तान यूनिलीवर, सांतवे नंबर पर भारती एयरटेल, आठवें स्थान पर आईटीसी, नौवें नंबर पर भारतीय स्टेट बैंक और दसवें स्थान पर बजाज फाइनेंस हैं।

मार्च से शेयरों का खरीद-बिक्री के दिन ही निपटान, सेबी चेयरपर्सन ने कहा- पूरी तरह से वैकल्पिक होगी नई प्रणाली

बोर्ड बैठक के बाद सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच ने बताया कि हम मार्च 2024 के अंत तक शेयरों की खरीद-बिक्री में टी प्लस जीरो (टी+0) निपटान नियम लागू करने की योजना बना रहे हैं। टी+0 का मतलब शेयरों का खरीद और बिक्री वाले दिन ही निपटान करना है। इसके 12 महीने बाद टी प्लस यानी तत्काल निपटान की व्यवस्था लागू की जाएगी।

मुंबई। पूंजी बाजार नियामक सेबी अगले वर्ष मार्च से शेयरों की खरीद और बिक्री वाले दिन ही निपटान प्रणाली पेश करने की योजना बना रहा है। इसके बाद तुरंत निपटान प्रणाली लागू की जाएगी। नियामक पहले ही शेयर निपटान की अवधि को घटाकर टी+1 (खरीद-बिक्री के अगले दिन निपटान) कर चुका है। बोर्ड बैठक के बाद सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच ने बताया कि हम मार्च 2024 के अंत तक शेयरों की खरीद-बिक्री में टी प्लस जीरो (टी+0) निपटान नियम लागू करने की योजना बना रहे हैं।

सुझावों पर भी विचार के लिए तैयार है सेबी

टी+0 का मतलब शेयरों का खरीद और बिक्री वाले दिन ही निपटान करना है। इसके 12 महीने बाद टी प्लस यानी तत्काल निपटान की व्यवस्था लागू की जाएगी। बुच के अनुसार, बाजार से जुड़े लोगों का मानना है कि टी+1 से सीधे तत्काल निपटान व्यवस्था पर जाना ज्यादा बेहतर होगा। टी+0 से कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सेबी तत्काल निपटान को लेकर दिए गए सुझावों पर भी विचार के लिए तैयार है।

सेबी ने इसी वर्ष जनवरी में लागू की थी टी+1 व्यवस्था

उन्होंने कहा कि नए निपटान नियम मौजूदा नियमों के समानांतर होंगे और पूरी तरह से वैकल्पिक होंगे। नए नियम चुनिंदा बड़े उत्पादों के लिए उपलब्ध होंगे और उसमें भी चयन करना वैकल्पिक होगा। सेबी ने इसी वर्ष जनवरी में टी+1 व्यवस्था लागू की थी। इससे पहले टी+2 निपटान व्यवस्था लागू थी। एक सवाल के जवाब पर पुरी ने कहा कि सेबी निश्चित रूप से आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) के अत्यधिक मूल्यांकन के मुद्दे पर विचार करेगा। इस सप्ताह पांच कंपनियों के आइपीओ में रिकार्ड 2.6 लाख रुपये के आवेदन मिले हैं।

सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियम बनाएगा सेबी

बोर्ड बैठक में सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामकीय फ्रेमवर्क तैयार करने का फैसला हुआ है। साथ ही नाट फार प्रोफिट आर्गेनाइजेशंस (एनपीओ) को सोशल स्टाक एक्सचेंज के जरिये पैसा जुटाने में आसानी के लिए नियमों में ढील दी गई है।

सेबी ने क्या कहा?

सेबी ने कहा कि एनपीओ की ओर से जुटाई जाने वाली न्यूनतम राशि को एक करोड़ से घटाकर 50 लाख कर दिया गया है। छोटी और मध्यम अवधि के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (एसएम-रीट्स) के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य वैकल्पिक निवेश फंड (एआइएफ) में निवेश करने वालों के हितों की रक्षा करना है। सभी एआइएफ के लिए कस्टोडियन की नियुक्ति को अनिवार्य बनाया है। सितंबर 2024 से एआइएफ में निवेश भी डीमैट से अनिवार्य किया गया है।

रविवार को इन शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुआ बदलाव, चेक करें लेटेस्ट रेट

तेल कंपनियों ने रविवार 26 नवंबर को सुबह 6 बजे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें को अपेडट कर दिया है। हालांकि तेल की कीमतें राष्ट्रीय स्तर पर मई 2022 से स्थिर बनी हुई हैं लेकिन तेल की कीमतों में तेल कंपनियों द्वारा रिवाइज के बाद कुछ पैसे का बदलाव जरूर देखा गया है।

नई दिल्ली। तेल कंपनियों ने रविवार 26 नवंबर के लिए देश के हर छोटे और बड़े शहरों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को आज सुबह 6 बजे रिवाइज किया है।

हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों को स्थिर रखा गया है, लेकिन कीमतों को अपडेट करने के दौरान कुछ शहरों में कुछ पैसों का बदलाव जरूर देखा जा रहा है। जानिए आपके शहर में क्या है तेल के दाम।

इन शहरों में तेल की कीमतों में हुआ बदलाव

गुड रिटर्न के मुताबिक आज तेल की कीमतें इस प्रकार हैं:

शहर	पेट्रोल (कीमत रुपये प्रति लीटर)	डीजल (कीमत रुपये प्रति लीटर)
नोएडा	96.65	89.82
गुरुग्राम	96.89	89.76
पटना	107.24	94.04
तिरुवनंतपुरम	109.73	98.53
भुवनेश्वर	103.19	94.76

इन शहरों में स्थिर रही कीमत

नई दिल्ली	96.72	89.62
कोलकाता	106.03	92.76
मुंबई	106.31	94.27
चैन्नई	102.63	94.24
लखनऊ	96.57	89.76
बेंगलुरु	101.94	87.89
चंडीगढ़	96.20	84.26
हैदराबाद	109.66	97.82
जयपुर	108.48	93.72

नवंबर में भी एफपीआई ने जारी रखी बिकवाली, पहले तीन कारोबारी सत्र में बेचे 3400 करोड़ रुपये से अधिक के शेयर

नई दिल्ली। नवंबर महीने के पहले तीन कारोबारी सत्र में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने पहले की तरह शेयर बाजार से बिकवाली जारी रखी है। 1,2 और 3 नंवबर के कारोबारी सत्र में एफपीआई ने 3,400 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी की है।

पिछले महीने कितने करोड़ की कि निकासी

इससे पहले के महीनों की बात करें तो अक्टूबर में एफपीआई ने कुल 24,548 करोड़ रुपये और सितंबर में कुल 14,767 करोड़ रुपये की निकासी की है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक, 1-3 नवंबर के दौरान एफपीआई ने 3,412 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। सितंबर की शुरुआत से ही एफपीआई बिकवाली कर रहे हैं। हालांकि निकासी से पहले, एफपीआई ने मार्च से अगस्त तक पिछले छह महीनों में शेयर बाजारों में लगातार खरीदी कर रहे थे और इस दौरान एफपीआई ने करीब 1.74 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया था।

एफपीआई क्यों कर रहे हैं बिकवाली?

विशेषज्ञों की माने तो बिकवाली के पीछे मुख्य कारण इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई को मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इंडिया के एसोसिएट डायरेक्टर - मैनेजर रिसर्च, हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि इसका मुख्य कारण इजरायल और हमास के बीच संघर्ष के कारण बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के साथ-साथ अमेरिकी ट्रेजरी बांड पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि है। बढ़ती बॉन्ड यील्ड और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा नवंबर की बैठक में नरम रुख का संकेत देने के बाद अब भारतीय शेयर बाजार से एफपीआई के अधिक निकासी की संभावना कम है।

फिटनेस न इमरजेंसी मेडिकल किट... 11 खटारा एंबुलेंस ब्लैक लिस्टेट, मरीजों की सौदेबाजी के बाद जगे जिम्मेदार

आगरा में डीएम की सख्ती के बाद एक दर्जन एंबुलेंस के खिलाफ कार्रवाई की गई। अवैध, अपंजीकृत, अनफिट एंबुलेंस के चालान काटे गए। इनसे एक लाखसे अधिक का जुर्माना वसूला गया।

आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा में आरटीओ और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खटारा मिलीं 11 एंबुलेंस को ब्लैक लिस्टेट कर दिया है। इन पर 1.04 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इनमें फिटनेस, बीमा और प्रदूषण विभाग की एनओसी नहीं थी। मरीजों के लिए इमरजेंसी मेडिकल किट समेत चिकित्सकीय उपकरण भी नहीं थे। बिना मानक के दोबारा चलते मिलने पर सील करने की चेतावनी दी गई।

सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि संयुक्त टीम ने एसएन मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी, पोस्टमार्टम हाउस, लेडी लायल और दिल्ली गेट पर टीम ने जांच की। इसमें 11 एंबुलेंस पकड़ी गईं। इनकी फिटनेस सालभर पहले ही खत्म हो गई थी। प्रदूषण नियंत्रण की एनओसी और बीमा भी नहीं था।

परिवहन विभाग के यात्री कर अधिकारी शिवशंकर मिश्रा ने 1.04 लाख रुपये जुर्माना वसूला है। एसीएमओ डॉ. एसके राहुल ने जब एंबुलेंस में चिकित्सकीय मानक परखे तो चौपट हाल मिला। इसमें ऑक्सीजन देने के लिए अंबू बैग, स्ट्रेचर, इमरजेंसी मेडिकल किट, अग्निशन यंत्र, बीपी मापक यंत्र, आला समेत अन्य चिकित्सकीय मानक नहीं थे।

मरीजों की सौदेबाजी के बाद आरटीओ की टूटी नींद

एसएन इमरजेंसी के बाहर फिरोजाबाद के मरीज को कमीशन के लिए भगवान टॉकीज स्थित श्री हरि हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में भर्ती कराने के मामले के बाद भी आरटीओ और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सक्रिय नहीं हुए। इस पर मुख्यमंत्री और डीएम की सख्ती के बाद अधिकारियों की नींद टूटी और जांच अभियान चलाया।

एसएन में निजी एंबुलेंस खड़ी मिलने पर पुलिस को सूचना

एसएन प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि 13 सितंबर को थाना एमएम गेट में पत्र भेजकर अनाधिकृत तरीके से एसएन परिसर और इमरजेंसी के बाहर खड़ी होने वाली एंबुलेंस को पकड़ने और चालकों पर कार्रवाई के लिए कह चुके हैं। स्टाफ को निर्देशित किया है कि निजी एंबुलेंस खड़ी मिले तो उसका नंबर नोट कर पुलिस को सूचना दें।

इन पर हुई कार्रवाई

यूपी 80, सीटी 0616
यूपी 40, सीटी 5489
यूपी 40, बीएम 9082
यूपी 80, डीटी 1924
यूपी 85 एटी 8291
यूपी 80 सीटी 5613
यूपी 80 एफटी 1517
यूपी 40 बीई 9363
यूपी 40 बीएम 9082
यूपी 83 टी 1260
यूपी 80 सीटी 1933

अब जीपीएस लगे वाहनों से मिलों तक धान की होगी ढुलाई

बस्ती। इस बार सरकार ने धान क्रय नीति में बदलाव किया है। इसके तहत ढुलाई करने वाले वाहनों में जीपीएस लगाए जाएंगे। सेवा प्रदाता कंपनी के इंजीनियर मंडल के तीनों जिलों में वाहनों में जीपीएस लगा रहे हैं। फिलहाल यह व्यवस्था बस्ती, संतकबीरनगर व सिद्धार्थनगर समेत प्रदेश के 40 जिलों में परीक्षण के तौर पर लागू की गई है। पूर्व में केंद्रों पर धान खरीदने के बाद परिवहन कार्य में लगे साधारण ट्रकों से मिलों तक धान पहुंचाया जाता था। ऐसे में कई तरह के आरोप-प्रत्यारोप लगते थे। केंद्र प्रभारियों का कहना रहता था कि केंद्र पर तौले गए धान व मिलों पर पहुंचने वाले खेप के तौल में अंतर आ जाता है। इससे मिलर्स व केंद्र प्रभारी के बीच विवाद की स्थिति बनी रहती थी। यही नहीं, कई बार गोलमाल की शिकायत भी मिलती थी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि कई ट्रक समय से मिलों तक नहीं थे। इससे केंद्र से भेजे जाने वाले धान के दिन व समय की सटीक जानकारी नहीं मिल पाती थी। शासन ने गेहूं व धान के खरीद समेत अनाज पहुंचाने की अधिकतर प्रक्रिया को ऑनलाइन कर री है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए शासन ने केंद्रों से मिलों तक परिवहन करने वाले वाहनों का टेंडर फाइनल कर दिया है।

हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगजनों के लिए अब आरक्षित होगी 10, 11 नंबर सीट

पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की सभी साधारण बसों में दिव्यांगजनों के लिए अब 10 और 11 नंबर सीट आरक्षित होगी। अब तक बसों में 2 और 3 नंबर सीट इस वर्ग के लिए आरक्षित होती थी।

नई दिल्ली। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की सभी साधारण बसों में दिव्यांगजनों के लिए अब 10 और 11 नंबर सीट आरक्षित होगी। अब तक बसों में 2 और 3 नंबर सीट इस वर्ग के लिए आरक्षित होती थी। बस चालक के कैबिन के पास होने के चलते 2 और 3 नंबर सीट पर उठने-बैठने में असुविधा के कारण आरक्षित सीटों में बदलाव किया गया है। अब दिव्यांगजनों के लिए बस के अगले दरवाजे के पीछे 10 और 11 नंबर सीट आरक्षित रहेगी। इन सीटों पर दिव्यांगजन आसानी से बैठ सकेंगे। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित सीटों में बदलाव को लेकर सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। सीट नंबर 10 और 11 के ऊपर दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित लिखवाने के भी निर्देश दे दिए हैं।

तेज रफ्तार स्कूटर ने हेड कॉन्स्टेबल की बाइक को मारी टक्कर, ड्यूटी से लौट रहे थे घर

दिल्ली के वसंत विहार इलाके के पास एक तेज रफ्तार स्कूटर ने दिल्ली पुलिस को हेड कॉन्स्टेबल को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में पुलिसकर्मी को सिर और कंधे में चोटें आईं हैं। पुलिस ने बताया कि ये सड़क हादसा 22 नवंबर को तब हुआ जब पुलिसकर्मी सरदूल अपने घर जा रहे थे। पुलिस ने अज्ञात स्कूटर सवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

नई दिल्ली। दिल्ली के वसंत विहार इलाके के पास एक तेज रफ्तार स्कूटर ने दिल्ली पुलिस को हेड कॉन्स्टेबल को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में पुलिसकर्मी को सिर और कंधे में चोटें आईं हैं।

पुलिस ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के वसंत विहार इलाके के पास कथित तौर पर एक तेज रफ्तार स्कूटर ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे दिल्ली पुलिस के 58 वर्षीय हेड कांस्टेबल घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि ये सड़क हादसा 22 नवंबर को तब हुआ जब पुलिसकर्मी सरदूल अपने घर जा रहे थे। पुलिस ने अज्ञात स्कूटर सवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

ड्यूटी कर घर लौट रहे थे पुलिसकर्मी

पीड़ित पुलिसकर्मी ने पुलिस टीम को बताया कि वह वर्तमान में मध्य जिले के संयुक्त पुलिस आयुक्त के कार्यालय में तैनात हैं और 22 नवंबर को ड्यूटी खत्म करने के बाद अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन चालक ने उन्हें टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया।

सरदुल ने अपनी पुलिस शिकायत में आरोप लगाया, जब मैं मुनिरका के पास पहुंचा तो गलत दिशा से आ रहे एक स्कूटर सवार ने मेरी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर के कारण मैं सड़क पर गिर गया और पैर, सिर और कंधे में चोटें आईं हैं।

लखीमपुर खीरी जा रही बस में लगी आग, मां बेटी समेत पांच घायल

टीकरी बॉर्डर से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जा रही निजी बस में आग लगने से बच्ची समेत पांच लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान सात वर्षीय बेटी रीमा लोंगम मेहरमा रतरारानी और गोपाल के रूप में हुई है। अस्पताल में इलाज के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई। पश्चिम विहार थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर बस चालक को पकड़ लिया।

पश्चिमी दिल्ली। टीकरी बॉर्डर से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जा रही निजी बस में आग लगने से बच्ची समेत पांच लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान सात वर्षीय बेटी रीमा, लोंगम, मेहरमा, रतरारानी और गोपाल के रूप में हुई है।

अस्पताल में इलाज के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई। पश्चिम विहार थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर बस चालक को पकड़ लिया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के कहमारा गांव के गोपाल ने पश्चिम विहार थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह हरियाणा के बहादुरगढ़ सेक्टर-छह के सामने ईंट, गारा का काम करते हैं। बुधवार को वह अपने बच्चों, पत्नी, सास व आसपास के लोगों के साथ हरियाणा से अपने गांव जा रहे थे।

उन्होंने कुल 15 लोगों के साथ टीकरी बॉर्डर से उत्तर प्रदेश के लिए निजी बस पकड़ी। बस निरंतर रूप से लखीमपुर खीरी से यहां व यहां से लखीमपुर जाती है। साढ़े छह बजे जब बस पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन के पास पहुंची तो बस की पिछली सीट पर अचानक से आग लग गई।

उन्होंने आग बुझाने के लिए बस में अग्निशमन यंत्र ढूंढे, लेकिन नहीं मिले। आपातकालीन दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वह भी बंद किया हुआ था, जो नहीं खुला। अचानक से आग लगने पर बस में भगदड़ मच गई व वह बस में नीचे गिर गए। जिस वजह से उन्हें भी चोट लगी व उनकी सात वर्षीय बेटी रीमा, उनकी पत्नी लोंगम, सास मेहरमा व गांव की ही महिला रतरारानी आग से झुलस गई।

इसके बाद पीरागढ़ी चौक पर खड़े रहने वाले दस से 15 किन्नर आए।वह आसपास की दुकानों से पानी लेकर आए व आग को बुझाया। बस में लगी आग बुझते ही चालक बस लेकर भाग गया। पुलिस मौके पर पहुंची व घायलों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।

किन्नर समय पर न पहुंचे तो बड़ा हो सकता था हादसा

गोपाल ने बताया कि बस में आग बुझाने के यंत्र नहीं थे। आपातकालीन द्वार भी नहीं खुला। अगर अग्निशमन यंत्र होते या फिर बस का आपातकालीन द्वार खुल जाता तो लोग आग की चपेट में आने से बच जाते। उन्होंने बताया कि जब वह परिवार को बचाने के लिए भागे तो नीचे गिर गए व दब गए। ऐसे में उन्होंने बताया कि अगर समय पर किन्नर न पहुंचते तो बड़ा हादसा हो सकता था। गोपाल ने बताया कि बृहस्पतिवार तड़के पुलिस चालक को पकड़कर थाने लेकर आई।

फोरलेन बनने से अब बसें दो घंटे जल्दी पहुंचेंगी दिल्ली लोगों की सुविधा के लिए कुछ रूटों में किया गया बदलाव

पहले मनाली से दिल्ली जाने वाली बसों में 12 घंटे का समय लगता था जो अब 10 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगी।

सुंदरनगर के हराबाग से कीरतपुर के लिए फोरलेन पर बसों की आवाजाही शुरू हो गई है। इससे अब दो घंटे का समय कम हो गया है। पहले मनाली से दिल्ली जाने वाली बसों में 12 घंटे का समय लगता था जो अब 10 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगी। बिलासपुर के लोगों को भी लग्जरी बस सेवाओं का लाभ मिल सके।

कुल्लू। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सुंदरनगर के हराबाग से कीरतपुर के लिए फोरलेन पर बसों की आवाजाही शुरू हो गई है। इससे अब दो घंटे का समय कम हो गया है। पहले मनाली से दिल्ली जाने वाली बसों में 12 घंटे का समय लगता था जो अब 10 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगी।

परिवहन निगम द्वारा सुंदरनगर कीरतपुर फोरलेन आरंभ होने पर परिवहन निगम की कुछ बसें सुंदरनगर से फोरलेन पर कुछ बसें वाया बिलासपुर गोणी होते हुए स्वारघाट से कीरतपुर से आने जाने के निर्देश दे दिए गए है।

निर्देशों के अनुसार बसें चलाई जा रही

परिवहन निगम द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार बसें चलाई जा रही है। परिवहन निगम की लग्जरी बसों में सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए मनाली से चलने वाली लग्जरी बस सेवाएं सुंदरनगर से कीरतपुर फोरलेन से चलाई जा रही है। इसके अलावा नेरचौक में लगने वाले जाम के मध्येनजर लग्जरी बसों को नेरचौक बाईपास से चलाया जाएगा।

बिलासपुर के लोगों को भी लग्जरी बस सेवाओं का मिलेगा लाभ

बिलासपुर के लोगों को भी लग्जरी बस सेवाओं का लाभ मिल सके। इसके लिए परिवहन निगम द्वारा कुछ रूटों में बदलाव किया गया है। मनाली से चलने वाली प्रत्येक लग्जरी बस नेरचौक बाईपास से जाएगी। नेरचौक के यात्री परिवहन निगम की लग्जरी बस सेवाओं को डडौर स्थान से ले सकते है।

इसके अलावा मनाली से दिल्ली शाम तीन बजे से नौ बजे तक चलने वाली लग्जरी बसें सुंदरनगर से कीरतपुर फोरलेन से चलाई जा रही है। जबकि मनाली से चंडीगढ़ सुबह आठ और शाम सढ़े सात बजे चलने वाली लग्जरी बस सेवाएं सुंदरनगर हराबाग से कीरतपुर फोरलेन से संचालित की जा रही है।

सुंदरनगर हराबाग से कीरतपुर फोरलेन से चलाई जा रही AC बस

मनाली से हरिद्वार शाम तीन बजे चलने वाली हिमधारा एसी बस सुंदरनगर हराबाग से कीरतपुर फोरलेन से चलाई जा रही है। इसके अलावा मनाली से दिल्ली शाम आठ बजे, मनाली से हरिद्वार शाम साढ़े चार बजे, मनाली से चंडीगढ़ सुबह 10 बजे चलने वाली लग्जरी बस सेवाएं बिलासपुर, नौणी, मंडी- भराडी फोरलेन से होते हुए हुए सचांलित की जा रही है।

बिलासपुर के यात्री जिन्होंने सुंदरनगर हराबाग से कीरतपुर फोरलेन होकर संचालित की जा रही लग्जरी बस में सफर करना है तो मंडी भराठी से परिवहन निगम की बस सेवाओं का लाभ उठा सकते है। इसी प्रकार नेरचौक के यात्री डडौर नामक स्थान से परिवहन निगम की उपरोक्त बस सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।

मनाली से दिल्ली जाने वाली बसों में समय सारणी में कुछ बदलाव किए गए हैं। फोरलेन बनने के बाद अब बसों का संचालन शुरू कर दिया है। इसमें दो घटें की बचत हो गई है। -डीके नारंग आरएम एचआरटीसी कुल्लू डिपो।

सुंदरनगर के हराबाग से कीरतपुर फोरलेन पर लग्जरी बसों का संचालन शुरू कर दिया है। इसके अलावा नेरचौक में लगने वाले जाम को देखते हुए लग्जरी बसों को नेरचौक बाईपास से चलाया जाएगा। कुछेक लग्जरी बस सेवाएं बिलासपुर रूट पर भी चलाई जा रही है। -रोहन चंद ठाकुर, प्रबंध निदेशक हिमाचल पथ परिवहन निगम शिमला।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023